।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5

● अंक-258

रायपुर, रविवार 14 जून 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

पेज-8› मेयर मीनल चौबे ने पंडरी कपड़ा...

फ्रांस में होगी पीएम मोदी-ट्रंप की मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के छह दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। पीएम मोदी इन दोनों देशों की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा करने के साथ ही फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे।

भारतीय पीएम की इस यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चर्चा काफी अहम रहेगी, लेकिन उनकी वैश्विक नेताओं के साथ होने वाली बैठकों पर नजर रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरे पर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से भी मिलेंगे। इस वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, %फ्रांस भारत की रणनीतिक दृष्टि में विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक ऊंचा उठाया था।नाइस में राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के दौरान हम फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के अगले कदम तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वे वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। यह दौरा फ्रांस के साथ भारत की गहरी साझेदारी को नई गति देने के साथ-साथ स्लोवाकिया के साथ ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने और जी-7 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का अवसर होगा।

भाजपा का पंजाब मिशन 2027

पंजाब में भाजपा अकेले लड़ेगी चुनाव

नईदिल्ली। 13 जून को नई दिल्ली में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद, भारतीय जनता पार्टी (क्ष्छ्क्ष) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की अपनी योजना की पुष्टि की है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पत्रकारों से कहा कि हमने पंजाब की राजनीति पर चर्चा की। यह बहुत अच्छी बैठक थी। पंजाब के लिए हमारा एकमात्र एजेंडा विकास है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे; अभी गठबंधन की कोई बात नहीं हो रही है। हम पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाएंगे।

बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी पंजाब की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए डबल-इंजन सरकार बनाने के मकसद से, बिना किसी गठबंधन के हर सीट पर चुनाव लड़ने की पार्टी की रणनीति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेता नितिन नवीन की अगुवाई में पंजाब बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के सामने मौजूद चुनौतियों, उनके समाधान और आने वाले चुनावों को लेकर लोगों की उम्मीदों पर चर्चा की गई। हमने इस बात पर विचार किया कि पंजाब को आर्थिक और सामाजिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे बहाल किया जाए। यह तय किया गया कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।बादल ने कहा कि मकसद 'डबल-इंजन' सरकार बनाना है; अगर 'डबल-इंजन' का नारा कहीं सफल हो सकता है, तो वह पंजाब है। आज की बैठक का मुख्य मकसद यही था। हमारा लक्ष्य पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाना है। इस बीच, बीजेपी नेता परमिंदर सिंह बराड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके की आलोचना की और कामकाज में सुधार के लिए चार महीने का अल्टीमेटम दिया। बराड़ ने फिर से कहा कि बीजेपी अपने दम पर अगली सरकार बनाएगी।बराड़ ने कहा कि बीजेपी सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। संदेश साफ है- बीजेपी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हम पंजाब की जनता के सामने अपना विज़न, एजेंडा और दूसरे राज्यों के रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और उनका दिल जीतेंगे। भगवंत मान ने राज्य को गिरवी रख दिया है।

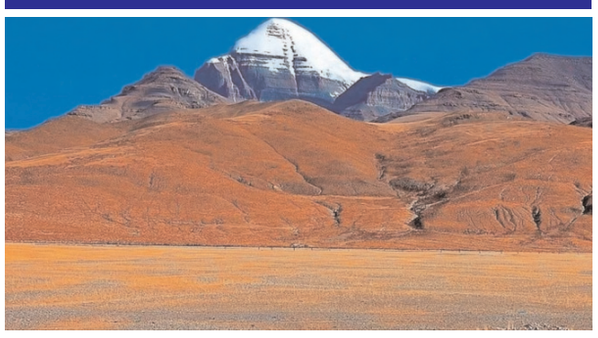

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होकर एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

(विस्तृत समाचार पेज-8 पर)

एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश, 5 जवान की मौत

रायपुर। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का ,ह-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के पांच वीर जवानों का निधन हो गया। यह हादसा विमान की नियमित उड़ान के दौरान लैंडिंग के समय हुआ। दुर्घटना में सह-पायलट घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया है।

सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारतीय वायुसेना के पांच वीर जवानों के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा के प्रति समर्पित इन वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

दुर्घटना में शहीद हुए जवानों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने इन सभी को कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाला वीर योद्धा बताया है। इस दुखद घटना पर देशभर में शोक की

पहले जत्थे को राज्यमंत्री मार्गरीटा ने दिखाई हरी झंडी

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026

नईदिल्ली। आस्था के सबसे कठिन और पावन सफर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का औपचारिक शंखनाद हो गया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में आयोजित समारोह के दौरान विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गरीटा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उद्घाटन समारोह के साथ ही शिवभक्तों की इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस साल यात्रा के लिए नाथू ला मार्ग को चुना गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों का यह पहला जत्था 15 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्ली से अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेगा।

नाथू ला दर्रे से बढ़ेगा कारवां

विदेश मंत्रालय इस पूरी यात्रा का संचालन कर रहा है। सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े प्रबंधों के बीच तीर्थयात्री आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से रवाना होने के बाद इस जत्थे का अगला पड़ाव सिक्किम होगा। नाथू ला मार्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुगम व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तीर्थयात्रियों में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार की ओर से यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

तैयारियों और सुरक्षा की अग्निपरीक्षा

कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में होती है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली में सभी यात्रियों की गहन चिकित्सा जांच की गई है। अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार इस यात्रा की निगरानी कर रहे हैं। इस रूट पर बुनियादी सुविधाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया है।

आस्था और कूटनीति का संगम

यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक विरासत का भी एक बड़ा हिस्सा है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आवेदन करते हैं। कड़े चयन मानदंड और मेडिकल टेस्ट के बाद ही भाग्यशाली तीर्थयात्रियों को भोलेनाथ के दर्शन का यह अवसर मिलता है। उद्घाटन समारोह में विदेश राज्यमंत्री ने सभी यात्रियों को सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

प्रमुख समाचार

अवैध आप्रवासन पर अमित शाह सख्त, अध्ययन का निर्देश

नईदिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज आबादी में बदलाव पर एक बैठक की अध्यक्षता की और आयोग को सीमावर्ती ज़िलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, श्री शाह ने आयोग को हालात का जायज़ा लेने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले पिछले महीने, केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से आबादी में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। अधिकारियों ने बताया कि समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने समिति से कहा कि वह अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से आए बदलावों का आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करे। इस कमिटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं।

नीट मामले के खिलाफ राहुल गांधी का राष्ट्रव्यापी शंखनाद

नईदिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) सहित देश की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं और छात्रों के हक में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस देश भर में छात्र सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद करेगी, जिसकी शुरुआत 17 जून को देश के सबसे बड़े कोचिंग हब राजस्थान के कोटा से होने जा रही है। इसके बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी वह इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इन छात्र सम्मेलनों के माध्यम से नीट के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करने, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी।

भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं राहुल गांधी : पिनाराई विजयन

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम पी. विजयन ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए विजयन ने कहा कि उनका राजनीतिक रवैया विपक्षी इंडी गठबंधन को मजबूत नहीं करता बल्कि कई बार इसका फायदा भाजपा को मिलता है। राहुल गांधी ने हाल ही में इंडी गठबंधन की बैठक में पी विजयन को राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण गले न लगाने की बात कही थी। राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयन ने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे गले लगाता है। विजयन ने दावा किया कि इंडी गठबंधन की बैठकों में केवल वामपंथी दलों ने ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य गैर-कांग्रेसी दलों के नेताओं ने भी कांग्रेस के रुख पर आपत्ति जताई थी। विजयन ने कहा, आज जो स्थिति बनी है, वह कांग्रेस और खासकर राहुल के रवैये की वजह से बनी है।

केरल सीएम को परिवार सहित जान से मारने की मिली धमकी

तिरवनंतपुरम। केरल में वीआईपी सुरक्षा और नेताओं को मिलने वाली धमकियों को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान अट्टिंगल निवासी सोनी थॉमस के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम छह बजकर 50 मिनट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने तिरुवनंतपुरम सिटी जिला पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में फोन कर दावा किया कि वह मुख्यमंत्री और उनके परिवार की हत्या कर देगा। इस संबंध में एक प्राथमिकी में कहा गया है कि जब उससे इसका कारण पूछा गया तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि उसे सतीशन पसंद नहीं हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने शाम छह बजकर 53 मिनट पर दोबारा फोन किया और फिर धमकी दी।

अभिषेक बनर्जी के पीए के आवास में पुलिस की छापेमारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए शनिवार का दिन भारी हलचल और कानूनी संकटों से भरा रहा। एक तरफ जहाँ पुलिस ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) सुमित रॉय की तलाश में उनके कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी की, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पार्टी के एक और कद्दावर विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। खबरों के मुताबिक, शालबोनी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस के जवानों के साथ मिलकर सुबह-सुबह तलाशी अभियान चलाया। तलाशी पूरी करने के बाद पुलिस टीम वहां से चली गई। इस घटनाक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचीं। सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी उन आरोपों से जुड़ी है जिनमें कहा गया है कि रॉय ने पार्टी का चुनावी टिकट दिलाने का वादा करके लोगों से पैसे लिए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस इन दावों की जांच कर रही है और इस मामले में रॉय की तलाश कर रही है। इन आरोपों को लेकर अभिषेक बनर्जी या उनके ऑफिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान

नीरज कुमार दुबे

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो रणनीतिक कदम उठाया था उसका असर अब पाकिस्तान के खेतों और उसकी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। भले पाकिस्तान पानी की कमी से त्राहि त्राहि कर रहा हो लेकिन भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कह दिया है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों तक भारत सिंधु का पानी नहीं पहुंचने देगा। हम आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दी है। सिंध और बलूचिस्तान में नहरें सूख रही हैं, खेत बंजर होने लगे हैं और किसानों में भारी बेचैनी फैल गई है।

पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के राजनीतिक नेता, किसान संगठन और जल विशेषज्ञ खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि यह केवल जल संकट नहीं, बल्कि आर्थिक कत्लेआम की शुरुआत है। सिंध, जहां कराची जैसा आर्थिक केंद्र मौजूद है, वहां पानी की कमी ने पूरे तंत्र को हिला दिया है। बलूचिस्तान के कई इलाके भी अब इसी तबाही की चपेट में हैं। यह संकट पाकिस्तान की लगभग एक तिहाई आबादी को प्रभावित कर रहा है।

देखा जाये तो भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केवल सैन्य जवाब नहीं दिया, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऐसी चोट की जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नई दिल्ली ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करके दुनिया को संदेश दिया कि आतंक फैलाने वालों को अब हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार अब अपने इरादे को केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की तैयारी भी तेज कर चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार सीमा पार पानी के

प्रवाह को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पाटिल ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत अब आतंकवाद को संरक्षण देने वालों तक सिंधु का पानी नहीं पहुंचने देगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब शांति की भाषा न समझने वालों को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है।

दूसरी ओर, जल की कमी का असर पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई ढांचे सुक्कुर बैराज पर साफ दिखाई दे रहा है। सिंधु नदी पर बना यह विशाल ढांचा लाखों एकड़ खेती को जीवन देता है। लेकिन अब यहां से निकलने वाली नहरों में पानी तेजी से घट रहा है। उत्तर पश्चिम नहर में 64 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई है। राइस नहर लगभग 38 प्रतिशत घाटे में चल रही है, जबकि दादू नहर की हालत सबसे भयावह है, जहां 82 प्रतिशत तक पानी कम हो चुका है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई नहरों में तय हिस्से का केवल एक चौथाई पानी पहुंच रहा है। दादू नहर को जहां लगभग पांच हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, वहां केवल आठ सौ साठ क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। उत्तर पश्चिम नहर को छह हजार से अधिक क्यूसेक के बदले केवल 2100 क्यूसेक पानी मिल रहा है। किसान धान की नर्सरी तक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। खेत सूख रहे हैं और गांवों में बेचैनी फैल रही है।

यहां एक और बात यह भी है कि पाकिस्तान के भीतर ही पानी की लूट और असमान वितरण ने भी आग में घी डाल दिया है। सिंध सिंचाई विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब अपने तय हिस्से से 21 प्रतिशत अधिक पानी खींच रहा है। तौंसा बैराज भी तय सीमा से ज्यादा पानी ले रहा है। दूसरी तरफ निचले इलाकों में नहरें सूख रही हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का आंतरिक ढांचा भी अब टूटने लगा है।

यही वजह है कि वहां राजनीतिक युद्ध छिड़ चुका है। जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध सरकार को पानी संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पीपुल्स पार्टी संघीय तंत्र और जल प्रबंधन एजेंसियों पर हमला बोल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता निसार अहमद खुह्रो ने खुलकर कहा है कि सिंध देश की 67 प्रतिशत कृषि उपज पैदा करता है, फिर भी उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने खरीफ मौसम में पानी कटौती को सिंध का आर्थिक कत्लेआम बताया।

सुशासन तिहार में जनसमस्याओं का लगा अंबार, एक माह में 42 हजार नक्शों का हुआ बटांकन

अब गांव-शहर चलो अभियान के जरिए जनता तक पहुंचेगा प्रशासन

मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिले में 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के दौरान प्रशासन ने जनसमस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान जिलेभर में 24 समाधान शिविर लगाए गए, जहां हजारों लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं। शिविरों में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले और विधायक धरमलाल कौशिक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान सबसे अधिक शिकायतें पेयजल और बिजली व्यवस्था से जुड़ी प्राप्त हुईं। ग्रामीणों ने बिजली कटौती, खराब ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन और जलापूर्ति की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

प्रशासन ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि जटिल प्रकरणों के लिए समय-सीमा तय कर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन तिहार के दौरान राजस्व विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि करीब 42 हजार नक्शा बटांकन का कार्य रहा। कलेक्टर ने बताया कि पिछले एक वर्ष से इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही थी, जिससे कई राजस्व प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही थीं। इसे देखते हुए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर राजस्व अमले को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। अभियान के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्शा बटांकन का कार्य पूरा किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जून माह के अंत तक जिले में नक्शा बटांकन का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि भूमि की खरीदी-बिक्री, सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए नक्शा बटांकन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस कार्य के पूरा होने से हजारों किसानों और भूमि स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि आगामी मानसून और मौसम परिवर्तन को देखते हुए सभी विभागों को प्रोएक्टिव मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयार रहने और पेयजल विभाग को जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग को जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन का दावा है कि सुशासन तिहार केवल शिकायतें सुनने का अभियान नहीं रहा, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित राजस्व कार्यों को गति देने का प्रभावी माध्यम भी साबित हुआ है। 42 हजार नक्शा बटांकन को प्रशासन इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर रहा है।सुशासन तिहार के समापन के बाद जिला प्रशासन ने अब गांव-शहर चलो अभियान को अपनी अगली प्राथमिकता बनाया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार आगामी 15 दिनों तक सभी विभागीय अधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण करेंगे और गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे।

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में बड़ा घोटाला ब्लैकलिस्ट फर्म को दिया करोड़ों का ठेका

डिप्टी सीएम अरुण साव बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट की जा चुकी कंपनी मेसर्स श्री कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को करीब 13 करोड़ रुपए के ठेके बांट दिए। मामला सामने आने के बाद राजनीति गरमा गई है।कंपनी ने टेंडर हासिल करने के लिए विभाग को झूठा शपथपत्र सौंपा, जिसे विभागीय अधिकारियों ने आंखें मूंदकर स्वीकार भी कर लिया। दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी के संचालक ने स्टांप पेपर पर लिखित दावा किया था कि उनकी फर्म किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2023 में ही इस कंपनी की निविदा सुरक्षा राशि (श्रस्ष्ठ) जब्त कर इसे ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया था।ब्लैकलिस्टेड के बाद भी विभाग ने बिलासपुर खेल परिसर और विद्युत नवीनीकरण कार्य के लिए मेसर्स श्री कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को करीब 4.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस पूरे घोटाले से राजनीति गरमाई हुई है। मामले में पीडब्ल्यू के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जांच के बाद कारवाई करने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की पिता की याचिका

बालिग बेटी को भी मिलेगा भरण-पोषण

बिलासपुर। बेटियों के अधिकार को लेकर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है, कि बालिग होने के बाद भी बेटी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पिता पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, खासकर जब पहले से ही फैमिली कोर्ट का आदेश लागू हो।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस टिप्पणी के साथ पिता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। जिसमें बेटी को हर महीने 5,000 रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

मामला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का है। याचिकाकर्ता गोरखनाथ यादव ने फैमिली कोर्ट मनेंद्रगढ़ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी बेटी कु। प्रिया को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने पहले 2016 में 2,000 रुपये प्रतिमाह की राशि तय की थी, जिसे बाद में 2023 में बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। याचिकाकर्ता पिता ने कोर्ट में दलील दी कि बेटी अब बालिग हो चुकी है और इसलिए भरण-पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची की मां के पास पर्याप्त कृषि भूमि और आय है, जिससे उसका पालन-पोषण संभव है। पिता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि बेटी उनकी वैध पत्नी की संतान नहीं है और पारिवारिक परिस्थितियों में भी मतभेद हैं। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, कि 2016 से लगातार भरण-पोषण आदेश लागू है। पिता ने पहले कभी इस आदेश को चुनौती नहीं दी।

चिल्फी घाटी में फिर चरमराई यातायात व्यवस्था

भारी-भरकम मशीन के सड़क पर गिरने से लगा लंबा जामज

कवर्धा। जिले की चिल्फी घाटी में एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। घाटी के नाग मोड़ी के पास ट्रक पर लादकर ले जाई रही मशीन के सड़क पर गिरने से ह्॥-30 रायपुर-जबलपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. जाम की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, जबलपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक में फैक्ट्री की भारी-भरकम मशीन ले जाई जा रही थी, तभी चिल्फी घाटी के नाग मोड़ी के पास अचानक मशीन ट्रक से गिरकर बीच सड़क पर आ गई। मशीन गिरने के बाद पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, सूचना मिलते ही चिल्फी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से मशीन हटाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन भारी मशीन होने के कारण यातायात बहाल करने में समय लग रहा है। यह पहला मौका नहीं है, जब चिल्फी घाटी में इस तरह की जाम की स्थिति बनी हो. ऐसी स्थिति गाहे-बगाहे बनती रहती है, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रशासन की ओर से अब तक इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

कवर्धा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव, पोखराज परिहार सातवीं बार अध्यक्ष

कवर्धा। कवर्धा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता पोखराज परिहार ने सातवीं बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर नया कीर्तिमान बनाया है। अधिवक्ता संघ के 70 साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी अधिवक्ता को सातवीं बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कवर्धा बार एसोसिएशन में कुल 180 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें से 172 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए इस बार दो उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से पोखराज परिहार को 110 वोट मिले, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रकाश चंद्रवंशी को 62 वोट मिले। इस तरह पोखराज परिहार ने 48 मतों के बड़े अंतर से एकतरफा जीत हासिल की। जीत के बाद कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला।जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखराज परिहार ने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कवर्धा बार परिवार की जीत है। उन्होंने कहा कि सातवीं पारी में उनकी प्राथमिकता जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण, स्टाइपेंड व्यवस्था शुरू कराना और बार भवन को डिजिटल स्वरूप देना है। उनका लक्ष्य कवर्धा बार को छत्तीसगढ़ का मॉडल बार बनाना है।

8 वाहन और मशीन जब्त, कोयला भंडारण डिपो सील अवैध उत्खनन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर शिकंजा कसा है। टीम ने अवैध खनन और परिवहन में लगे 8 वाहनों के साथ ही मशीनों को भी जब्त किया है। इतना ही नहीं एक कोयला डीपो को भी सील कर दिया गया है। बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की खनिज टीम को गतौरी गांव स्थित बालाजी कोल ट्रेनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के कोयला भंडारण डिपो में कोयले की गुणवत्ता में मिलावट और भंडारण शर्तों का उल्लंघन की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद जब टीम ने छापा मारा, तो शिकायत सही पाई गई।

इस दौरान मौके से 01 ट्रेलर और 01 जेसीबी मशीन जब्त किया गया। साथ ही अनियमितता मिलने पर संचालित भंडारण डिपो को तत्काल सील कर दिया गया। जब्त वाहन और मशीन को कोनी थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है।

इसी कड़ी में सकरी, कोटा, विजयपुर, दर्री और तखतपुर क्षेत्रों में सघन जांच अभियान के दौरान बिना वैध दस्तावेज खनिज परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। दर्री-विजयपुर क्षेत्र से गिट्टी का अवैध परिवहन करते 01 हाइवा, सकरी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 01 हाइवा और गिट्टी परिवहन करते 01 अन्य हाइवा को पकड़ा गया। वहीं खोंगसरा क्षेत्र में अरपा नदी से अवैध रेत उत्खनन करते 03 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भिलाई में केंद्र और राज्य की योजनाओं की दी गई जानकारी

दुर्ग। जिले के भिलाई नगर निगम द्वारा बैकुंठ धाम स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में एक दिवसीय लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा छोटे व्यापारियों, फेरी व्यवसायियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय, उत्तर रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक, हितग्राही, बैंक अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थित देखी गई। मेले में प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के पहले चरण में 15 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार

बिलासपुर। व्यापार विहार में दिनदहाड़े व्यापारी को झाड़ फूंक का झांसा देकर ठगी की वारदात सामने आई है। खरीदारी करने पहुंचे एक व्यापारी का 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर बाइक सवार दो बदमाश फरार हो गए। व्यापारी के बेटे उमेश कुमार साहू ने बताया कि जिस समय उनके पिता के साथ यह घटना हुई वह कुछ दूरी पर थे। उमेश साहू ने बताया कि लहसुन, प्याज सहित अन्य कृषि उत्पादों की थोक खरीदारी के लिए दोनों पिता पुत्र 3 लाख लेकर व्यापार विहार पहुंचे। इसी दौरान उनके पिता से दो बाइक सवार बात करने लगे। आरोपियों ने पहले व्यापारी को अपनी बातों में उलझाया और तबीयत ठीक करने का झांसा देकर कुछ कदम आगे चलने के लिए कहा। इसी दौरान मौका मिलते ही आरोपी उनका रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बुजुर्ग ने कुछ दूर तक आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से व्यापारी हक्का-बक्का रह गया और उन्होंने शोर मचाया, और पीछे दौड़े लेकिन तब तक आरोपी तेज रफ्तार बाइक से मौके से फरार हो चुके थे।

रतनपुर के तालाब में मगरमच्छ, अंडों से निकले 6 बेबी क्रोकोडाइल

बिलासपुर। धार्मिक नगरी रतनपुर के बिकमा तालाब में सुबह उस समय लोगों में कौतूहल मच गया, जब तालाब के बाहर मगरमच्छ के 6 बच्चे दिखाई दिए। मगरमच्छ ने तालाब किनारे अंडे दिए थे, जिनसे बच्चे बाहर निकले। सुबह तालाब में नहाने पहुंचे लोगों ने जब मगरमच्छ के बच्चों को देखा तो इसकी सूचना तत्काल रतनपुर पुलिस और वन विभाग को दी। तालाब में मगरमच्छ होने की सूचना मिलते पर रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।इस दौरान वार्ड पार्षद मनोज कुमार पाटले भी मौके पर उपस्थित रहे। पार्षद ने बताया कि इसकी सूचना रतनपुर थाने में और वन विभाग को दी गई। जिसके बाद मगरमच्छ के बच्चों को फॉरेस्ट विभाग को सौंपा गया। पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ के बच्चों को सुरक्षित वन विभाग कार्यालय ले जाया गया, जहां से वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित खुटाघाट डैम में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि तालाब के किनारे बड़े बड़े अंडे दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद मैं वहां पहुंचा तो अंडों से मगरमच्छ के बच्चे निकल रहे थे।

1 करोड़ से ज्यादा की ठगी दो बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर। पीएसएल चिटफंड कंपनी ने लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देते हुए कई लोगों से कंपनी में इंवेस्ट कराया। कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की चाहत में कई लोग फंस गए और अपनी जमा पूंजी चिटफंड कंपनी में लगाई। पैसे जमा करने की समय अवधि पूरी होने के बाद भी लोगों के पैसे वापस नहीं कराए गए, जिसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। सूरजपुर डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि कोतवाली थाना में साल 2016 में पीएसएल चिटफंड कंपनी के 10 डायरेक्टरों के उपर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का आरोप दर्ज हुआ। ठगी के इस मामले में सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे दो आरोपी गुरजंट सिंह गिल और गुरनाम सिंह को कवर्धा में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट के आधार पर सूरजपुर लाया गया। दोनों आरोपियों की उम्र लगभग 77 और 80 साल है। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं।

जगदलपुर के पुराने फिल्टर प्लांट में भीषण आग

जगदलपुर। शहर के नयामुण्डा स्थित पुराने फिल्टर प्लांट और पानी टंकी परिसर में शुक्रवार शाम करीब 8 बजे अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक किरण सिंह देव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर या विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़की। जिससे परिसर में रखे ब्लीचिंग पाउडर और अन्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, नगर निगम का अमला और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय विधायक किरण देव ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

जल संरक्षण के लिए लोहारी ग्रापं ने बड़ा कदम

मनरेगा से तैयार हो रहा जल संरक्षण का मॉडल

एमसीबी। गर्मी के मौसम में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ग्राम पंचायत लोहारी ने भविष्य की बड़ी चुनौती से निपटने की दिशा में एक सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार सूखते जलस्रोत और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पंचायत ने बारिश के पानी को सहेजने का अभियान शुरू किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत गांव में कंटूर ट्रेंच और अर्दन गुलीपलक निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

इसका उद्देश्य बारिश के दौरान बहकर बर्बाद होने वाले पानी को रोकना और उसे जमीन के अंदर पहुंचाकर भूजल स्तर को बढ़ाना है। ग्राम पंचायत लोहारी क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्य आने वाले समय में ग्रामीणों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। पंचायत ने अब तक 504 कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया है, जिसमें करीब दो लाख लीटर पानी संरक्षण होने की संभावना है।

इसके साथ ही अर्दन गुलीपलक निर्माण के माध्यम से लगभग एक लाख लीटर पानी रोकने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। इन संरचनाओं से बारिश का पानी धीरे-धीरे जमीन में समाएगा, जिससे जलस्तर में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय ग्रामीण राम सजीवन साहू ने बताया कि लोहारी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या काफी बढ़ जाती है। कई जलस्रोत सूख जाते हैं और ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गर्मी के अंतिम दौर में कई बार टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में बारिश के पानी को रोकने की यह पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े का कहना है कि जल संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिले में मनरेगा के माध्यम से डबरी, कुएं, तालाब गहरीकरण, सामुदायिक तालाब और वाटर रिचार्ज जैसे कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बारिश की हर बूंद को बचाकर धरती में समाहित किया जा सके।

बालोद कलेक्टर का बड़ा आदेश, जिला कार्यालय के पास धारा 163 लागू

बालोद। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर और उसके आस पास के क्षेत्रों में अब बिना अनुमति के भीड़ जुटाना या प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है। कानून व शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। यह आदेश 12 जून से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन के मुताबिक, अक्सर विभिन्न संगठनों या दलों के 20 से 25 या उससे अधिक लोग ज्ञापन सौंपने के बहाने जिला कार्यालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान भारी शोर शराबा और नारेबाजी होती है, जिससे न केवल कार्यालय की शांति भंग होती है, बल्कि शासकीय कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। कई बार कलेक्ट्रेट परिसर में ही कानून-व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इसी माहौल को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह सख्त कदम उठाया गया है।

एक जगह 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जमा- कलेक्ट्रेट के 500 मीटर के दायरे में किसी भी जगह पर 4 या उससे ज्यादा एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। हथियार ले जाने की मनाही- ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति (चाहे उसके पास लाइसेंस ही क्यों न हो) विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र या धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।हालांकि, धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। तोड़फोड़ और पुतला दहन पर सख्त मनाही- प्रदर्शन के दौरान शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन करना, टायर जलाकर रास्ता रोकना या जनता में दहशत फैलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नए आदेश के मुताबिक यदि किसी संगठन को रैली, जुलूस या प्रदर्शन करना है, तो उन्हें पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह नियम सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघों और आम जनता पर समान रूप से लागू होगा। कलेक्टर ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह का शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय एवं निरंतर संवाद की भावना ने विकास कार्यों को नई गति प्रदान की है। इसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना विकास, उद्योग, रोजगार, कौशल विकास तथा जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी सहयोग और समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में सहायता प्राप्त होगी। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय आ जांजगीर चांपा जिले को देंगे विभिन्न विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 14 जून को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जांजगीर-चांपा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय सत्य निज नाम बोध संस्थान पोड़ी (राछा) में आयोजित सत्य निज नाम सत्संग सम्मलेन में भी शामिल होंगे। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि जिले के प्रभारी एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विशिष्ट अतिथि छ.ग. विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, सांसद जांजगीर-चांपा श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप, विधायक अकलतरा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, विधायक पामगढ़ श्रीमती शेषराज हरबंश, विधायक जैजैपुर श्री बालेश्वर साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, अध्यक्ष छ.ग. खनिज विकास निगम श्री सौरभ सिंह, पूर्व संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री गगन जयपुरिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ श्रीमती कांता कश्यप, ग्राम पंचायत पोड़ी सरपंच श्रीमती सरोजनी आशिकर होंगे।

पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में लगी आग

रायपुर। पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है। घटना उरला थाना क्षेत्र की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में सैंपल लेने के दौरान वाल्व बंद नहीं होने से गर्म पदार्थ बाहर बह गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सेल्फ इग्नीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे आग भड़क उठी। घटना के दौरान सैंपल ले रहे एक कर्मचारी के हाथ में हल्की चोट आई है। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में कुछ समय के लिए धुएं का गुबार छाया रहा। फिलहाल प्रबंधन व पुलिस मौके पर मौजूद हैं, मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी अधिकृत तौर पर नहीं दी गई है।

ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर उरकुरा स्टेशन में संरक्षा सेमिनार

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन हेतु परिचालन, विद्युत परिचालन, इंजीनियरिंग तथा सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के साथ उरकुरा स्टेशन में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई- शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियां तथा लोड गाडियों का स्टेशन/यार्ड में सिक्योरिंग एवं रिलिजिंग करना, स्पैड से बचाव एवं ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक टिकट द्वारा ट्रेन की कार्यप्रणाली, इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा मानसून के पहले बरती जाने वाली सावधानियां,पॉइंट्स एवं सिग्नल की विफलता के दौरान परिचालन एवं सिग्नल कर्मचारियों के द्वारा बरती जनेवाली सावधानियां, हाल ही में हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण, तथा अग्निशामक यंत्र का उपयोग एवं प्रदर्शन। इस संरक्षा सेमिनार में सुरेश चन्द्र, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/रायपुर एवं प्रवीण कुमार, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी/रायपुर के साथ- संरक्षा सलाहकारो ने संरक्षा सेमिनार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरक्षा संगठन/रायपुर मंडल के द्वारा प्रत्येक माह में 02 संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन रायपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों में किया जाता है, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने के दौरान संरक्षा के प्रति जागरुकता लाई जा सके।

पीएम मोदी के नेतृत्व में समृद्ध और सशक्त भारत का हो रहा है निर्माण: मुख्यमंत्री

मोदी ने दुनिया में भारत के झंडे को किया ऊंचा : गिरिराज सिंह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश की तीन करोड़ की जनता की ओर से आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के ध्येय वाक्य के साथ उनके नेतृत्व में समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा नया भारत, जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं हैं।

मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। 2014 में देश के केवल 7 राज्यों में बीजेपी, एनडीए थी। अब देश के 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। जो जनता के विश्वास का परिणाम है। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं थे। आज 58 करोड से ज्यादा खाते हैं। 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के नाम पर बैंक खाता है। कोरोना के समय से भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बना है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत कई लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी 10 लाख 60 हजार पीएम आवास योजना का लाभ मिला। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंचा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2014 से पीएम ने जब घोषणा की तो विरोधी लोग उपहास उड़ा रहे थे कि क्या पीएम जैसे लोग शौचालय बनवाते हैं। आज उनके मुंह बंद हो गए। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लोगों को लोन मिला है। 12 सालों में जनजातीय लोगों का सम्मान हुआ है। राष्ट्रपति के पद पर जनजातीय समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को फायदा मिल रहा। उनके राशन कार्ड बन रहे, पीएम आवास योजना का लाभ उन्हें मिलता है। जनजातीय समाज के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का लाभ मिल रहा है। जनजातीय लोगों के विकास के लिए

आदिम जाति कल्याण का अलग से विभाग है। पहले खेती करने के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं थी। आज किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। 3 करोड़ से ज्यादा माता बहने लखपति बनी हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को फायदा मिल रहा है। लोगों के घरों में सोलर लगाया जा रहा है। 12 वर्षों में गरीबों के कल्याण के काम हुए हैं। देश के विकास के लिए वे 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत विकास के काम हो रहा है। 12 वर्षों में चार लाख किलोमीटर सड़कें बनी है। किसानों के विकास के लिए भी सरकार संकल्पबद्ध है। पीएम सिंचाई योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ा है। 1 l46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग में बढ़ोतरी हुई। दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास पहुंचा है। विश्व के सबसे ऊंचा ब्रिज अटल टनल पवन ब्रिज बनाने का काम हुआ। रेलवे स्टेशन के विकास के काम हो रहे हैं। रेलवे का बजट पीएम के नेतृत्व में 21 गुना बढ़ा। 1 हजार 95 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है। 12 साल में 90 हवाई अड्डे बने अब 164 हवाई अड्डे है। पीएम चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करें जिसके तहत लोगों को भी लाभ मिला है। जगदलपुर अंबिकापुर में भी हवाई यात्रा शुरू हुई है। 12 साल में 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को ही लेने का काम किया 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। वन नेशन, वन टैक्स के जरिए देश के लोगों को लाभ मिला। 16 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ तक बजट लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने दुनिया के सामने भारत की इकॉनोमी को चौथे नंबर पर लाने का काम किया। विदेशी मुद्रा कोष 724 बिलियन तक गए। एफडीआई 304 बिलियन डॉलर से 863 बिलियन डॉलर पर लाने का काम किया। एक्सपोर्ट आज 82 लाख करोड़ का है। लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता। या तो चश्मा बदल लें। ये एक ऐसे पक्षी है, जिसको दिन में दिखाई ही नहीं देता, उसके लिए मैं दोषी नहीं। देश के लोग पीएम मोदी को प्यार करते हैं। कांग्रेस के लोग 'इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे कहते थे' गरीबी नहीं मिटी, गरीब जरूर मिट गए।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि युवराज कलावती के घर में गरीबी सीखने गए थे। मीडिया को भी लेकर गए थे। वे भी रात भर जागे। पीएम मोदी गरीब के घर में ही पैदा हुए। जो लोग गाली दे रहे हैं, वे हार का शतक मनाएं। कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा किया है। पूरे दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है।

महक की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय : सीएम साय

■ मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजनांदगांव जिले की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर सुश्री महक नरवासे ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह तथा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए टी-20 एवं वनडे दोनों टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर सुश्री महक नरवासे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर महक का सम्मान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महक नरवासे की यह उपलब्धि केवल उनके परिवार या राजनांदगांव जिले की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रही हैं। महक ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जो प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महक आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम गौरवान्वित करेंगी।

उन्होंने महक को प्रोत्साहित करते हुए कहा, खूब खेलो, आगे बढ़ो और नई ऊंचाइयों को छुओ। आपकी सफलता प्रदेश के हजारों युवा खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महक नरवासे का भारतीय अंडर-19 महिला टीम की उपकप्तान के रूप में चयन प्रदेश में विकसित हो रहे खेल वातावरण और खिलाड़ियों को मिल रहे अवसरों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सुश्री महक नरवासे ने सम्मान एवं शुभकामनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके पिता श्री राधेश्याम नरवासे, महापौर श्री मधुसूदन यादव, कोच श्री मनोज तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम की तारीफ का बड़ा असर- सोशल मीडिया पर वीडियो देख रायपुर से जीपीएम पहुंचे ग्राहक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पारंपरिक विष्णु भोग चावल की तारीफ किए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हालत यह है कि अब जिले के बाहर से भी लोग इस विशेष सुगंधित चावल को खरीदने के लिए उत्पादकों तक सीधे पहुंच रहे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मरवाही विकासखंड की ग्राम पंचायत निमधा में आयोजित जनचौपाल के दौरान स्थानीय किसानों और महिला समूहों द्वारा उपजाए गए विष्णु भोग चावल की विशेष सराहना की थी। मुख्यमंत्री के इस संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसी वीडियो को देखकर रायपुर निवासी अजय कुमार इस पारंपरिक चावल की विशेषताओं और गुणवत्ता से इतने प्रभावित हुए कि वे अपने साथियों के साथ सीधे

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले पहुंच गए।

जिले में पहुंचे इन ग्राहकों ने कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन की विशेष उपस्थिति में तिपान महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से सीधे 50 किलोग्राम विष्णु भोग चावल की खरीदी की। इस खरीदी की कुल कीमत 7 हजार रुपये रही। रायपुर से आए ग्राहकों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा उत्पाद की तारीफ किए जाने के बाद ही उनकी रुचि इस चावल के प्रति जगी थी और वे खुद इसकी सुगंध और स्वाद का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने भविष्य में भी इस चावल की खरीदी जारी रखने की बात कही।

इस मौके पर तिपान महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति रंग ला रही है। इससे किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों और उत्पादक संगठनों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है और उनके लिए बाजार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

अपनी विशिष्ट सुगंध, बेहतरीन स्वाद और उच्च गुणवत्ता के लिए पहचाना जाने वाला विष्णु भोग चावल अब सिर्फ एक स्थानीय फसल नहीं, बल्कि जिले की कृषि समृद्धि और महिला उद्यमिता का एक सफल ब्रांड बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री की इस अनूठी पहल से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीदें काफी मजबूत हो गई हैं।

स्कूल खुलने की तारीख बढ़ाने का आदेश फर्जी

■ मंत्री गजेंद्र यादव बोले - 16 जून से ही खुलेंगे स्कूल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में स्कूलों के खुलने की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आदेश को पूरी तरह फर्जी बताया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने की निर्धारित तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूल 16 जून 2026 से ही खुलेंगे और इस संबंध में विभाग की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा पत्र फर्जी और भ्रामक है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसे अपुष्ट दस्तावेजों पर विश्वास न करें और केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों को ही मान्य मानें।

मंत्री यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग वायरल पत्र की जांच कर रहा है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रसारित करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वायरल आदेश में एक जुलाई से स्कूल खुलने की बात कही गई है, जो पूरी तरह फर्जी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। प्रदेश में 16 जून को प्रत्येक स्तर पर शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

शौर्य चक्र से सम्मानित वीर जवानों से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित वीर पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों से उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने नवा रायपुर अटल नगर स्थित निवास कार्यालय में आत्मीय मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर डीजीपी श्री अरुण देव गौतम सहित जवानों के परिजन एवं परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए असाधारण परिस्थितियों में भी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुलाकात के दौरान श्री शर्मा ने शौर्य चक्र

से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तथा राइफलमैन भोज राम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की और उनके परिजनों से भी मुलाकात की और सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश सेवा के इस गौरवपूर्ण योगदान में परिवारों का त्याग और समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस भरी घटनाओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट एवं इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को 16 अप्रैल 2024 को कांकेर क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित एक बड़े अभियान में अद्वितीय नेतृत्व, साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय देने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। इसी प्रकार 3 असम राइफल्स के राइफलमैन भोज राम साहू को भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अदम्य साहस के साथ मोर्चा संभालते हुए दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने और अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान, कल्याण और उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अटल विहार बना आदर्श आवासीय परिसर

75.39 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है सुनियोजित आवासीय परिसर

रायपुर। घर केवल ईंट और सीमेंट से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि वह परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव होता है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी अटल विहार योजना ने कोरबा जिले के सैकड़ों परिवारों के लिए इस सपने को साकार कर दिखाया है। अपने घर का सपना संजोए अनेक परिवार आज कोरबा नगरीय क्षेत्र के झगरहा में विकसित अटल विहार कॉलोनी में आत्मविश्वास और संतोष के साथ जीवन बिता रहे हैं। यह आवासीय परिसर आज इस बात का प्रमाण है कि सुनियोजित आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार भी बनता है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 75 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 19 एकड़ में यह आवासीय परियोजना विकसित की गई है। विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां कुल 335 स्वतंत्र आवासों एवं फ्लैट भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसमें 50 एच.आई.जी., 18 सीनियर एम.आई.जी., 32 जूनियर एम.आई.जी., 75 एल.आई.जी. तथा 160 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों सहित प्रकोष्ठ भवन का

निर्माण शामिल है।

परियोजना के अंतर्गत अब तक 305 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और उनका चरणबद्ध हस्तांतरण किया जा रहा है। वर्तमान में 22 एच.आई.जी. तथा 5 सीनियर एम.आई.जी. भवनों का हस्तांतरण भी जारी है। यह उपलब्धि केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

अटल विहार कॉलोनी में अब तक 184 आवास हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं, जहां परिवार पिछले तीन वर्षों से शांत, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में निवास कर रहे हैं। पक्की सड़कें, बेहतर आधारभूत सुविधाएं, नियोजित आवासीय परिसर और सामुदायिक वातावरण ने यहां के निवासियों को एक नई जीवन शैली प्रदान की है। जिन परिवारों के लिए स्थायी आवास कभी एक चुनौती था, उनके लिए अटल विहार आज आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का पर्याय बन चुका है।

वर्तमान में कॉलोनी में एक व्यवसायिक भू-खण्ड, 4 एच.आई.जी. भवन तथा 103 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट भवन क्रय के लिए उपलब्ध हैं, जिससे और अधिक परिवार अपने घर के सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं।

झगरहा स्थित अटल विहार कॉलोनी न केवल आवास निर्माण की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, बल्कि यह राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण भी है। यहां बसते परिवार इस बात के साक्षी हैं कि गुणवत्तापूर्ण आवास किस प्रकार जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित

रायपुर। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला रायगढ (छ.ग.)
(ई-मेलः eewrdmj@cgwrd.in)

शुद्धि पत्र क्र.-02

निविदा सूचना क्र. 01/ व. ले. लि./ 2026-27, दिनांक 29.05.2026, निविदा सिस्टम नं. 191813 (प्रथम आमंत्रण), जी नम्बर 262701095 में प्रकाशित कार्य का निविदा की लागत 241.61 लाख (रू. दो करोड़ इकतालीस लाख इकसठ हजार) मात्र (GST छोड़कर) है।

निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

जी-262701400/9

बहुत कठिन डगर है परिसीमन विधेयक की!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की चुनावी पराजय के बाद भाजपा खेमे में परिसीमन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत अभी भी उसके पास नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व इस विषय को आगे बढ़ाने के प्रति उत्साहित दिखाई देता है। लोकसभा में एनडीए के पास वर्तमान में 292 सांसद हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस के कथित 20 बागी सांसदों का समर्थन भी मान लिया जाए, तो यह संख्या 312 तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। विशेषकर इसलिए क्योंकि डीएमके जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल परिसीमन के मौजूदा प्रस्तावों को लेकर गंभीर आपत्तियां रखते हैं। डीएमके की असहमति के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, पार्टी भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक से दूरी बना चुकी हो, लेकिन उसने एनडीए का हिस्सा बनने के संकेत भी नहीं दिए हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण परिसीमन की प्रकृति को लेकर उसका राजनीतिक दृष्टिकोण है। डीएमके का मानना है कि जनसंख्या आधारित नई सीटों का पुनर्वितरण दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है और उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकता है। परिसीमन का प्रश्न केवल संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि संघीय संतुलन का भी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों का तर्क है कि उन्होंने दशकों पहले केंद्र की नीतियों के अनुरूप जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया। यदि अब सीटों का बंटवारा मुख्यत: जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है, जबकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अतिरिक्त राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसी कारण तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों में यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि परिसीमन से संसद में उनकी सापेक्ष शक्ति कमजोर हो सकती है। डीएमके का सुझाव है कि यदि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई भी जाएं, तो राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर लगभग यथावत रखा जाए। पार्टी चाहती है कि इस सिद्धांत को केवल राजनीतिक आश्वासन नहीं बल्कि कानूनी संरक्षण भी मिले। दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने एक फ्लैट 50 प्रतिशत मॉडल का उल्लेख किया है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राज्य की वर्तमान सीटों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। इस मॉडल के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़कर 816-850 के बीच पहुंच सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी और दक्षिणी राज्यों को भी पर्याप्त अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर लगभग 59 तथा दक्षिण के पांच राज्यों की कुल सीटें 129 से बढ़कर लगभग 195 हो सकती हैं। हालांकि दक्षिणी दलों का कहना है कि केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उन्हें संवैधानिक और कानूनी गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार एक वर्किंग पेपर में लोकसभा की सीटें लगभग 824 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए 170 बड़े संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है, जिनमें 111 सीटों को तीन हिस्सों और 59 सीटों को दो हिस्सों में विभाजित करने की बात कही गई है। यदि इसी दिशा में आगे बढ़ा जाता है, तो दक्षिणी राज्यों में भी सीटों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती है- तमिलनाडु 39 से 59, कर्नाटक 28 से 42, केरल 20 से 30 और तेलंगाना 17 से 26 तक पहुंच सकते हैं।

राम मंदिर के चंदे में घपले की कहानी

अभिनय आकाश

राम जन्मभूमि भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और जटिल मुद्दा है, जिसको लेकर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसेटिव हो जाते हैं। इस एक विवाद की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दंगे हुए और इसमें हजरों लोगों की जान गई। ये एक ऐसा केस था, जहां पर भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा उनकी फाइल बनती है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर जिसके निर्माण के लिए कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। भक्तों की आस, कार्तिक के मास में रामलला का वनवास खत्म हो जाता है। रामलला के नाम जमीन के हक पर सुप्रीम हस्ताक्षर के साथ ही बड़े धूम धाम के साथ इसकी आधारशीला रखी गई और फिर मंदिर बनकर तैयार हो गया। जिसके उद्घाटन को पूरे देश ने एक ऐतिहासिक पल की तरह देखा। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राजनीति से लेकर आम श्रद्धालुओं तक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले चढ़ाने और दान के हिसाब-किताब में घड़बड़ी हुई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर में आए चढ़ावे में पांच करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक की कथित चोरी हुई है। भाजपा के ही नेता और पार्टी प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अब इन दावों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यलय यानी पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सबकुछ ठीक है तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में कोई घोटाला हुआ है? पीएमओ तक पहुंचे इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज का एमआरआई हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन, आरोपों, ट्रस्ट के जवाब और अब तक सामने आए तथ्यों को विस्तार से करेंगे।

मामले की शुरुआत 7 जून को हुई। तब पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडेय ने चढ़ावे में 5-7 करोड़ की चोरी का दावा किया। इसके बाद अखिलेश ने भी मुद्दे को उठाया और सरकार व ट्रस्ट की चुप्पी को संदिग्ध बताया। नौ जून को भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने पीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी आयोध्या पहुंचे लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। मंदिर के पूर्व अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने दावा किया कि लंबे समय से गड़बड़ी हो रही थी। उन्होंने शीर्ष प्रबंधन से इसकी शिकायत की। कार्रवाई के बजाय उन्हें पद से हटा दिया गया। दरअसल खुद को पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में एक दावा किया है। आरोप लगाया है कि जब वह मंदिर में तैनात थे तब चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी के जेवर और बर्तनों का कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। यह कहां जमा होते थे इसकी जानकारी सिर्फ चंपत राय और टिन्नू को होती थी। टिन्नू चंपत राय के नजदीकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिन्नू उर्फ रामशंकर यादव पहले चंपत राय के ड्राइवर अब उनके सहयोगी हैं। महिपाल ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि के लिए जब फंड कलेक्शन का काम शुरू हुआ तब मैंने काम संभाला। मेरा काम देखकर ही मुझे अयोध्या बुलाया गया। मैं अयोध्या गया तो 21,000 ऐसी रसीदें जारी होनी थी जो 7 आठ महीने से जारी नहीं हो पा रही थी।

इस मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ा समाजवादी पार्टी के दावे के बाद। सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कोई सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस पर सफाई दी। कहा कि समय-समय पर ऑडिट होता रहता है। आजकल यही काम चल भी रहा है। अब तक दान के पैसों में हेराफेरी की कोई बात सामने नहीं आई है। चंपत राय की सफाई के बाद अखिलेश यादव ने सरकार से 11 सवाल पूछे। पूछा कि सीसीटीवी का सबूत सार्वजनिक करके मामले की सच्चाई बताने में आखिर परेशानी क्या है? मामला बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की जांच रिपोर्ट भी मांग ली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, राम मंदिर में शिला पूजन के समय से चोरी जारी है। निर्माण शुरू हुआ तो दो-दो मिनट में प्लॉट की कीमतें करोड़ों बढ़ गई। वहां चंपत राय बैठे हैं... चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। आपको समझ जाना चाहिए।

राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह ट्रस्ट बना कैसे था। दरअसल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार को राम मंदिर के निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। इसी के बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। यही ट्रस्ट आज राम मंदिर के निर्माण, उसके रखरखाव, मंदिर में आने वाले दान और पूरे राम जन्मभूमि परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ट्रस्ट बनने के कुछ दिनों बाद इसकी पहली बैठक हुई। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। जबकि चंपत राय को महासचिव बनाया गया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। देश भर के लोगों ने खुलकर दान दिया। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने हजारों और लाखों रुपए दिए। बड़े उद्योगपति से लेकर आम श्रद्धालुओं तक लाखों लोगों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 204-25 में ट्रस्ट को कुल ?327 करोड़ मिले। यह डाटा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है। ?327 करोड़ में से 153 करोड़ श्रद्धालुओं के दान से आए। जबकि लगभग ?173 करोड़ बैंक में जमा रकम और निवेश पर मिले ब्याज के थे। सिर्फ दान की बात करें तो मंदिर में रोजाना औसतन करीब 42 लाख का चढ़ावा आता है। यानी हर घंटे लगभग ?175000 और हर मिनट करीब ?2900 से भी ज्यादा और जब त्यौहार हो या कोई खास मौका हो, बड़ा मौका हो तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। मंदिर के उद्घाटन वाले दिन ही लगभग 3 करोड़ 17 लाख का दान आया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितनी बड़ी मात्रा में दान आता है, नकदी आती है। राम जन्मभूमि परिसर में अलग-अलग जगहों पर करीब 40 दान पेटियां रखी गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दान की भी व्यवस्था है। दान पेटियों से निकली नगदी को तय प्रोसीजर के तहत एक सुरक्षित और गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। वहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में इसकी गिनती होती है। इस काम में ट्रस्ट के प्रतिनिधि और बैंक से जुड़े कर्मचारी शामिल रहते हैं। जानकारी के मुताबिक दान की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। बैंक ने इसके लिए एक निजी एजेंसी के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया हुआ है। नोट गिनने की मशीनों और सिक्कों की मैनुअल गिनती के जरिए पूरी रकम का हिसाब किया जाता है। कई बार गिनती या नगदी इतनी ज्यादा होती है कि गिनती का काम 24 घंटे तक भी चलता रहता है। गिनती पूरी होने के बाद रकम को सुरक्षा के बीच बैंक में जमा करा दिया जाता है।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। इनका कहना है कि मंदिर के चढ़ावे और दान का नियमित ऑडिट होता है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। चंपत राय के मुताबिक दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और अब तक हुए हर ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे करोड़ों रुपए की चोरी की पुष्टि होती हो। यानी एक तरफ विपक्ष और कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि पूरी व्यवस्था तय नियमों के अनुसार चल रही है और आरोपों का कोई आधार नहीं है। यानी इस समय तक स्थिति यह है कि आरोप लगाए जा चुके हैं। राजनीतिक बयान आ चुके हैं। जांच की मांग उठ चुकी है और अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुका है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

समाधान

इस श्लोक का अर्थ आपने खाक भी नहीं समझा। किसी सनातन-धर्मी विद्वान् के चरणों में बैठकर कुछ दिन साहित्यशास्त्र का अध्ययन कीजिये तब विशेष्य, विशेषणों की अन्वय शैली का बोध होगा।

सुनिये इस श्लोक में कूट-संयुक्ता: जो पद है वह शिल्पी आदि हर एक विशेष्य का विशेषण है और इसका अयं धोखेबाज है। सो कदाचित् हथियार बनाने वाले कारीगर, जीवन के रखवाले वैद्य, सोने वगैरा की कानों के इन्चार्ज, और सेना के अग्रभाग में झण्डा उठा कर आगे पीछे बढ़ने का इशारा करने वाले आफिसर मालिक को धोखा देने वाले हों तो वे नरकगामी होते हैं, यही इसका भाव है।

थोड़ी सी समझ रखने वाला मनुष्य भी समझ सकता है कि इस श्लोक में जिन चार पदाधिकारियों का जिक्र किया गया है वे अत्यन्त विश्वासपात्र तथा ईमानदार होने चाहियें । यदि भूल से धोखेबाज मनुष्यों को इन पदों पर नियत कर दिया जाय तो वे राष्ट्र का सर्वनाश कर सकते हैं।

शस्त्र बनाने वाले कारीगर शत्रु से मिल कर कच्चे लोहे के ऐसे हथियार बना सकते हैं जो कि सेना को ऐन मौके पर असफल कर दें विश्वासघाती वैद्य श्रौषधि के स्थान में बिना किसी रुकावट के जहर मिला सकता है।

खानों के इन्चार्ज गुप्त रीति से शत्रु को आर्थिक मदद दे सकते हैं। झण्डा उठाने वाला गलत सङ्केत देकर अपनी ही सेना को शत्रु की तैयार की हुई खन्दक में गिरा सकता है।

पुराणों की उपर्युक्त शिक्षा कितनी धर्मसंगत, एवं राष्ट्र को सम्भव विपत्ति से सावधान करने वाली है यह कोई भी समझदार तत्काल समझ सकता है।

क्रमशः ...

रक्तदान कर जीवन रक्षा का पुण्य कमाएं

मुकेश कुमार शर्मा

जीवन में हर किसी को कभी न कभी परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों या पड़ोसियों के लिए विशेष परिस्थितियों में रक्त (ब्लड) की आवश्यकता पड़ती ही है। कई बार हमें जरूरत के मुताबिक़ समय से सुरक्षित रक्त मिल जाता है तो कई बार समय से रक्त मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीज की जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।

विश्व रक्तदाता दिवस को मनाने का मूल मकसद लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है ताकि किसी भी मुसीबत में फंसे अपने ही नहीं पराये को भी समय से सुरक्षित रक्त मिल सके और उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी लैब में या किसी अन्य तरीके से तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज इस दिवस पर प्रण लेने की जरूरत है कि हम समय-समय पर रक्तदान कर महादानी बनने का गौरव हासिल करेंगे। इसके साथ ही आज उन महादानियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने और सम्मान करने का भी दिन है जिनके दान की बदौलत हर साल न जाने कितने लोगों के प्राणों की रक्षा की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है- दान का उत्सव मनाने के 20 साल = रक्तदाताओं को धन्यवाद।

18 से 65 साल का कोई भी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति रक्तदाता बन सकता है। रक्तदाता की कुछ जरूरी जांच भी की जाती है ताकि ब्लड बैंक तक किसी तरह से संक्रमित रक्त न पहुँचने पाए, इसीलिए हाल ही में टैटू बनवाने वालों व बीमार व्यक्तियों के रक्त लेने से भी परहेज किया जाता है ताकि रक्त की शुद्धता बरकरार रखी जा सके। वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4.5 लीटर से पाँच लीटर रक्त होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति एक बार में 300 से 450 मिली लीटर रक्त दान कर सकता है, जिसकी भरपाई शरीर 24 से 48 घंटे में खुद कर लेती है। तीन माह के अन्तराल पर दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। रक्त के अलग-अलग समूह होते हैं, जिनमें कुछ अति दुर्लभ किस्म के होते हैं, जिनके रक्तदाताओं की पहचान कर उनसे बराबर सम्पर्क में रहने की जरूरत होती है ताकि किसी विषम परिस्थिति में उनसे सम्पर्क कर रक्तदान की अपील की जा सके।

दुर्घटनाओं में घायलों, गर्भवती, सर्जिकल वाले मरीजों, थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया आदि स्थितियों में मरीज के लिए रक्त की जरूरत अस्पतालों को आये दिन रहती है। ऐसे में सुरक्षित और पर्याप्त रक्त का संग्रह चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे रक्तदाता के जरिये ही पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए रक्तदान से जुड़ीं भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर करने के साथ खुद रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। तो आइये हम सभी मिलकर आज इस पुनीत दिवस पर प्रण लें कि हम लोगों की जान बचाने के लिए खुद रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने के साथ ही स्वस्थ स्वास्थ्य परम्परा का भी निर्वहन करेंगे।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ता अविश्वास

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की कूटनीति में विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने जिस प्रकार राजनीतिक, सैन्य और मानवीय सहयोग प्रदान किया, उसने दोनों देशों के बीच मैत्री और विश्वास की मजबूत नींव रखी। पिछले पाँच दशकों में व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, संपर्क, जल संसाधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति तथा बांग्लादेश की विकासोन्मुख विदेश नीति ने भी संबंधों को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव और अविश्वास के संकेत दिखाई दिए हैं। यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध केवल रणनीतिक हितों से संचालित नहीं होते, बल्कि उनमें संवेदनशीलताओं, जनभावनाओं और पारस्परिक सम्मान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है।

भारत और बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध मौजूद हैं। पिछले एक दशक में भूमि सीमा समझौता, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा व्यापार तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बांग्लादेश आज भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

हाल के समय में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हुए बदलावों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की भूमिका को लेकर अलग-अलग धारणाएँ विकसित हुई हैं। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक समूहों में यह धारणा बनी कि भारत किसी विशेष राजनीतिक शक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति रखता है, जबकि भारत अपनी ओर से स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देने की बात करता रहा है। इस प्रकार की धारणाएँ चाहे तथ्यात्मक रूप से सही हों या नहीं, वे विश्वास के वातावरण को प्रभावित करती हैं और संबंधों में मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न करती हैं। तीस्ता नदी के जल बँटवारे का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी का जल कृषि और आजीविका की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से प्रस्तावित समझौता विभिन्न कारणों से लंबित है, जिससे बांग्लादेश में यह भावना विकसित हुई है कि उसकी चिंताओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका भी इस विषय को जटिल बनाती है, लेकिन समाधान में देरी ने अविश्वास को बढ़ावा दिया है। जल संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन के बिना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण कठिन प्रतीत होता है।

सीमा संबंधी मुद्दे भी संबंधों में तनाव का कारण बने हैं। तस्करी, अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों के कारण कई बार सीमा पर अप्रिय घटनाएँ हुई हैं। नागरिक हताहतों की घटनाओं ने बांग्लादेश में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है और भारत की छवि पर भी प्रभाव डाला है। यद्यपि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ समन्वय बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं, फिर भी ऐसी घटनाएँ आम लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएँ पैदा करती हैं। पड़ोसी देशों के बीच सीमा केवल सुरक्षा का विषय नहीं होती, बल्कि मानवीय और सामाजिक संबंधों से भी जुड़ी होती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मुद्दों ने भी बांग्लादेश में कुछ आशंकाएँ उत्पन्न कीं। यद्यपि भारत ने बार-बार स्पष्ट किया कि ये उसकी आंतरिक नीतियाँ हैं, फिर भी बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त की गई कि इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीतियों की वास्तविकता के साथ-साथ उनकी सार्वजनिक धारणा भी महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि ऐसे मुद्दे कभी-कभी कूटनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता भी भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बांग्लादेश ने अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन सहित कई देशों के साथ आर्थिक और अवसंरचनात्मक सहयोग बढ़ाया है। भारत के लिए यह स्वाभाविक चिंता का विषय है कि क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति का अत्यधिक प्रभाव उसके रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखते हुए विभिन्न देशों से निवेश और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना चाहता है। इस स्थिति में दोनों देशों के लिए पारदर्शिता और संवाद अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं।

व्यापारिक असंतुलन भी अविश्वास के कारकों में शामिल है। यद्यपि द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका लाभ अपेक्षाकृत अधिक भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। बांग्लादेश लंबे समय से भारतीय बाजार में अपने उत्पादों की बेहतर पहुँच तथा गैर-शुल्क बाधाओं में कमी की मांग करता रहा है। आर्थिक संबंधों में असंतुलन की भावना यदि लंबे समय तक बनी रहे तो वह राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आर्थिक साझेदारी को अधिक संतुलित और समावेशी बनाना समय की आवश्यकता है।सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने भी संबंधों को प्रभावित किया है। आज गलत सूचनाएँ, भ्रामक प्रचार और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री बहुत तेजी से फैलती है। कई बार छोटी घटनाएँ भी डिजिटल मंचों पर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे वातावरण में सरकारों और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे तथ्यपरक संवाद को बढ़ावा दें और दुष्प्रचार पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों और पड़ोसी देशों की संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित करे। एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति होने के कारण भारत की नीतियों का प्रभाव उसके पड़ोसियों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इसलिए केवल राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है; पड़ोसी देशों की आशंकाओं और अपेक्षाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा चिंताएँ, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों को एक-दूसरे की वैध चिंताओं का सम्मान करना होगा।

विश्वास बहाली के लिए सबसे पहले लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में ठोस पहल आवश्यक है। तीस्ता जल समझौते को प्राथमिकता देकर दोनों देश एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। सीमा प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना, संयुक्त गश्त और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना भी आवश्यक है। व्यापारिक असंतुलन को कम करने के लिए बांग्लादेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। ऊर्जा, परिवहन और संपर्क परियोजनाओं को गति देकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक परस्पर निर्भर बनाया जा सकता है।

आज का इतिहास

1962 फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम बाद में बदल कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर दिया गया।

1966 यू.एस. लूनर ऑर्बिटर को चंद्रमा के परिदृश्य की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था ताकि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र परिदृश्य पर उतरने के लिए तैयार किया जा सके।

1975 फिल्म द रॉकी हॉरर पिक्चर शो, जो आज भी रिलीज़ किया गया है, यह लॉस एंजेलिस में सबसे लंबे समय तक चलने वाली थिएट्रिकल रिलीज़ फिल्म का इतिहास है।

1980 डांस्क शिपयार्ड में लेच वाल्सा और उनके सहयोगियों ने हड़तालें शुरू कीं, जिसके बाद पोलैंड में सॉलिडैरिटीओवमेंट की स्थापना हुई।

1994 अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े कार्लोस द जैकल, यूरोप में एक नंबरऑफ आतंकवादी हमलों के लिए चाहते थे, फ्रांसीसी एजेंटों बायसुदानी अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

1995 ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी, IRNA का कहना है कि ईरान ने 200 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की बिक्री नहीं की है क्योंकि अमेरिका ने मंजूरी दी है।

1999 थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए।

2005 हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 ग्रीस के उत्तर मैराथन और वर्नाव के एक पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सभी 121 लोग मारे गए।

2006 संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान वारबेटन लेबनान और इज़राइल में युद्ध विराम का उल्लंघन किया।

2007 चीन के गोवी रेगिस्तान में पक्षिनुमा विशाल डायनसोर के जीवाश्म मिले।

2007 मध्य एशियाई देशों के शंघाई सहयोग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, जो सुरक्षा के मुद्दों पर बात करने के लिए बिश्केक की किर्गिज़ राजधानी में मिलते हैं।

2007 चार समन्वित आत्मघाती बम हमलों में काहतनिया और जजीरा के इराकिटाउन में विस्फोट हुआ, जिसमें 796 लोग मारे गए और 1,562 अन्य घायल हो गए।

2008 संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2008 में .8 प्रतिशत बढ़ जाता है, वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 5.6 प्रतिशत, 17 वर्षों में सबसे अधिक है।

2009 पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मालगाड़ी सेवा शुरू की।

भारत-नेपाल रिश्तों में समझदारी जरूरी

डॉ. सौरभ

पिछले दो हफ्तों में नेपाल के सत्तारूढ़ दल आरएसपी, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा उसके बाद विदेश मंत्री शिशिर खनाल की नयी दिल्ली यात्रा दोनों देशों के संबंधों की घनिष्ठता को ही दर्शाती है। नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद हुए आम चुनाव में बालेंद्र शाह जवाबदेही और सुशासन को आधार बनाकर अपूर्व जन समर्थन हासिल करते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने पार्टी अध्यक्ष तथा विदेश मंत्री को एक के बाद एक नयी दिल्ली भेजना यह इशारा करता है कि भारत के साथ संबंधों को नेपाल एक नयी दिशा देने के लिए बेहद उत्सुक है।

अपने भारत दौरे पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रमुख रवि लामिछाने ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की, वहीं दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी आपसी हितों और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता जतायी। गौरतलब है कि दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात मॉरीशस में हुए हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान भी हुई थी, जिसमें भारत ने अपनी 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत उच्च स्तरीय सहयोग बढ़ाने तथा सहयोग की गति बनाये रखने पर जोर दिया था।

तथ्य यह है कि नेपाल में पिछली कई सरकारों ने सत्ता बचाये रखने के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनी ढाल बनाया तथा कालापानी-लिंपियाधुरा मानचित्र विवाद उभार कर, नेपाली नोटों पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शा कर, भगवान राम की जन्मस्थली पर विवाद पैदा कर तथा अग्निवीर योजना आदि पर आक्रामक राजनीतिक राष्ट्रवाद का प्रदर्शन कर दोनों देशों के बीच अविश्वास का वातावरण बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ अविश्वास की खाई चौड़ी हुई है। यह उम्मीद करनी चाहिए कि बालेंद्र शाह सरकार आपसी विश्वास और सहमति से इन मुद्दों को सुलझायेगी।

पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने भारत और नेपाल में आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल असर डाला है। नेपाल ईंधन आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है, जबकि आपूर्ति शृंखला में किसी भी प्रकार का व्यवधान मुद्रास्फीति बढ़ाने के साथ-साथ वस्तुओं की लागत को भी प्रभावित करता है। होर्मुज संकट के दौरान भी भारत ने नेपाल को तेल की लगातार आपूर्ति बनाये रखी है। साथ ही, सीमावर्ती इलाकों में नेपाली वाहनों को तेल भी उपलब्ध करा रहा है। यह सहयोग की उस भारतीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो कोविड के समय विभिन्न देशों की मदद करते हुए भी दिखाई पड़ी थी।

नेपाल के विदेश मंत्री अगले सप्ताह चीन का दौरा करने वाले हैं। शिशिर खनाल की उस यात्रा को भारत और चीन के साथ संतुलन

बनाये रखने की नेपाल की कूटनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बालेंद्र शाह सरकार अपनी बुनियादी विकास परियोजनाओं, विशेषकर चीन से जुड़ी परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। इनमें से कई परियोजनाएं बेल्ट एंड रोड पहल से जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर भारत ने भी समय-समय पर चिंता जतायी है। गौरतलब है कि नेपाल ने 2017 में चीन के साथ बीआरआइ फ्रेमवर्क पर दस्तखत किये थे। चीन ने दावा किया है कि बीआरआइ के तहत नेपाल में पोखरा, लुंबिनी हवाई अड्डा, वी चेट पे क्रॉस बॉर्डर भुगतान सेवा, काठमांडू-तिब्बत रेलवे आदि पर दोनों देश सहमत हैं। दूसरी ओर, भारत ने अपने क्षेत्र की संवेदनशीलता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुंबिनी और पोखरा हवाई अड्डों पर हवाई यातायात हेतु अपने वायु सीमा क्षेत्र का उपयोग करने की नेपाली कोशिशों पर सहमति नहीं जतायी है, जो स्वाभाविक ही चीन की उपस्थिति के कारण है।

हम जानते हैं कि चीन की बीआरआइ परियोजना ने, जिनमें सड़कों, जलविद्युत संयंत्रों और व्यापार गलियारों का व्यापक निर्माण शामिल है, वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के समक्ष ऋण जाल का संकट खड़ा किया है। नेपाल में भी चीन अपनी परियोजनाओं द्वारा ऋण जाल फैलाकर उसकी संप्रभुता पर हमला करता है। बालेंद्र शाह सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 'पारदर्शिता' और 'जवाबदेही' पर जोर दिया है, जिसके तहत मौजूदा समझौतों की गहन जांच शुरू हुई है। परियोजनाओं की समीक्षा दरअसल यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि वे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों और वित्तीय बोझ न डालें।

नेपाल भले ही चीन और भारत के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहता है, परंतु भारत-नेपाल के मध्य खुली सीमा, आर्थिक अंतर्निभरता, सांस्कृतिक एकात्मकता, भाषायी समरूपता और भौगोलिक जुड़ाव सहयोग और भागीदारी के अनेक द्वार खोलता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेंद्र शाह अभी तक अपने समकक्ष किसी भी नेता से नहीं मिले हैं। उधर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिशों में है। बालेंद्र शाह ने कूटनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय मुद्दों को फिलहाल मंत्रियों और नौकरशाही के स्तर तक ही सीमित रखा है।

उग्र यथार्थवादी हितों वाले वैश्विक दौर में एक युवा नेता के दृष्टिकोण से यह उचित ही है कि वह पहले संवेदनशील मुद्दों पर सभी अनुरूप 'हितों' का आकलन करें और फिर कोई निर्णय लें। नेपाल जैसे देश के लिए यह सतर्क रवैया स्वाभाविक ही है, जिस पर कई देश अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। नेपाल की नयी सरकार भारत के साथ संबंधों को नयी ऊंचाई देने के लिए काफी उत्सुक है, परंतु ठोस प्रगति तो तभी होगी, जब दोनों देश लिये गये निर्णयों पर तेजी से अमल करेंगे।

जहां तक आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की बात है, तो उसमें नेपाल को भारत की संवेदनशीलता और सुरक्षा आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा। भारत हमेशा से ही सीमा से संबंधित मामलों को द्विपक्षीय आधार पर हल करने का पक्षधर रहा है। वह किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को कभी मंजूरी नहीं दे सकता। इस संबंध में अनावश्यक बयानबाजी दोनों देशों के संबंधों में अवरोध पैदा करती रही है। इससे दोनों ही पक्षों को बचना होगा।

संवाद और आपसी समझ के माध्यम से आपसी मतभेद दूर करने के लिए दोनों ही देशों के पास संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, जो भौगोलिक-आर्थिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग की नयी कहानी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष मजबूत राजनीतिक ताकत और इच्छाशक्ति के साथ आपसी संबंधों को नया आयाम देने में सक्षम हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री जल्दी ही भारत की यात्रा पर आयेंगे तथा शताब्दियों पुराने संबंधों को नयी दिशा देंगे, जो आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होगा, साथ ही, 'मनभेद' दूर कर जुड़ाव के नये क्षेत्रों को खोलेगा।

पीओके की पीड़ा: दमन की इंतहा, अधिकारों की मांग के जवाब में मिली गोलियां

नितिन गौतम

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान वहां की पुलिस व सुरक्षाबलों ने आम नागरिकों के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता दिखाई, वह मानवाधिकारों के लिहाज से तो गंभीर चिंता का विषय है ही, यह कश्मीरियों के हितैषी होने के उसके दावे की भी कलई खोलने वाला है। पिछले कुछ दिनों में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तीस से अधिक लोगों की जानें गई हैं, जिनमें बच्चे व गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं।

संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन राजनीतिक अधिकारों, विधायी प्रतिनिधित्व और आटे व बिजली की बढ़ती कीमतों जैसे स्थानीय मुद्दों से जुड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने जैसा दमन चक्र चलाया, वह इस्लामाबाद की व्यवस्थागत क्रूरता का ही जीवंत प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ही वहां के लोगों को न तो पूर्ण नागरिक अधिकार दिए गए, और न ही विकास की कोई सच्ची पहल हुई। बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ-साथ करों का भारी बोझ और संसाधनों का दोहन स्थानीय आक्रोश के प्रमुख कारण रहे हैं। इसकी तुलना में भारत द्वारा प्रशासित जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे, पर्यटन, निवेश, शिक्षा और स्थानीय संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में काफी सक्रिय रहा है।

यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय कश्मीर से अपनी तुलना करने पर पीओके के लोगों में असंतोष और बढ़ा होगा। जो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर

लगातार कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देता रहता है, उसके अपने कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर उसका रवैया इस्लामाबाद के दोहरे मापदंडों को ही उजागर करता है। यह देखते हुए कि पीओके की यह स्थिति कोई आज की नहीं है, इस मामले में अतीत में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया अपेक्षया कमजोर ही रही है।

हालांकि ताजा हिंसा पर चिंता जताते हुए ब्रिटेन के पचास सांसदों ने अपने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन इस मामले में अन्य महाशक्तियों की चुप्पी अखरने वाली है। पीओके या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही ऐसी मौतें व हिंसा की जांच न केवल वहां के लोगों के प्रति न्याय का प्रश्न है, बल्कि मानवाधिकारों की वैश्विक विश्वसनीयता से भी जुड़ा मुद्दा है। पीओके में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, वह वहां की दुर्दशा के बारे में भारत के दावे की ही पुष्टि करता है। ऐसे में, एक तरफ, यह भारत के लिए भी अवसर है कि वह पूरी दुनिया के समक्ष पीओके की वास्तविक स्थिति को तथ्यों व प्रमाणों के साथ अधिक सक्रियता से रखे, तो दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी मानवाधिकारों से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रुख अपनाना चाहिए।

मोदी सरकार के 12 वर्ष: उपलब्धियां, बदलाव और बहस के मुद्दे

सत्येंद्र प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो प्रथम आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़ा था।

पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिन पद पर रहते हुए देश का नेतृत्व किया था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 4,399 दिन पूरे कर इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है।

यदि प्रधानमंत्री के कुल कार्यकाल की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब भी सबसे आगे हैं। वे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। इस प्रकार उनका कुल कार्यकाल लगभग 6,130 दिनों का रहा।

इसमें 1947 से 1952 तक का अंतरिम सरकार का काल तथा 1952 के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल दोनों शामिल हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने नेहरू का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है, न कि प्रधानमंत्री के कुल कार्यकाल का रिकॉर्ड।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने केंद्र में अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि को समर्थक, भारत के शासन, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका में एक निर्णायक बदलाव के दौर के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक इसके कुछ नीतिगत और संस्थागत प्रभावों पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में इन 12 वर्षों का मूल्यांकन उपलब्धियों और चुनौतियों, दोनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

2014 में सत्ता संभालने के समय सरकार ने नीतिगत गतिरोध, धीमी परियोजना क्रियान्वयन और कल्याणकारी

योजनाओं में रिसाव जैसी समस्याओं को प्रमुख चुनौती बताया था। इसके बाद जन धन योजना, आधार और मोबाइल के संयोजन पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को विस्तार दिया गया। सरकार का दावा है कि इससे लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुंची और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी।

आर्थिक मोर्चे पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे कदमों को संरचनात्मक सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया गया।

समर्थकों का तर्क है कि इनसे औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा। हालांकि जीएसटी के शुरुआती क्रियान्वयन, छोटे कारोबारों पर प्रभाव और रोजगार सृजन की गति को लेकर बहस भी जारी रही।

सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि इन कार्यक्रमों ने जीवन स्तर में सुधार और गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने में योगदान दिया है।

कोविड-19 महामारी इस कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती रही। महामारी के दौरान मुफ्त राशन वितरण, नकद सहायता और वैक्सीनेशन अभियान को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है। दूसरी ओर, महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य ढांचे पर पड़े दबाव और उससे जुड़े अनुभवों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़े किए।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अधिक आक्रामक और निर्णायक दृष्टिकोण अपनाने का दावा किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर इसी परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं। समर्थकों के अनुसार इससे भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, जबकि आलोचक कुछ निर्णयों के दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करते हैं।

विदेश नीति में भारत की सक्रिय भूमिका, जी20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में प्रस्तुति तथा प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों का विस्तार इस अवधि की उल्लेखनीय विशेषताएं रही हैं। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल में वृद्धि हुई है।

डिजिटल परिवर्तन भी इस दौर की प्रमुख पहचान बना। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने वित्तीय लेनदेन के तरीके को बदल दिया और भारत को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के वैश्विक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। आज डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं की पहुंच और स्टार्टअप इकोसिस्टम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं।

इन 12 वर्षों का समग्र आकलन यह दर्शाता है कि भारत ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, डिजिटल शासन, आधारभूत संरचना और वैश्विक उपस्थिति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। साथ ही रोजगार, आय असमानता, कृषि संकट, संघीय संबंधों और संस्थागत संतुलन जैसे मुद्दे भी राजनीतिक एवं सार्वजनिक बहस के केंद्र में बने हुए हैं।

बहरहाल, मोदी सरकार के 12 वर्षों को केवल उपलब्धियों या केवल आलोचनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर के रूप में देखा जाना चाहिए जिसने भारतीय राजनीति, शासन और विकास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया है।

इंडिया गठबंधन: बिखराव के बीच एकजुटता की राह कैसे निकलेगी?

हरि वर्मा

सुखेंदु शेखर के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह जल्द भाजपा की हो जाएंगी। 28 वर्षों के संघर्ष से उपजी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है। चुनाव नतीजे के महज एक महीने बाद ही पार्टी में बगावत इस कदर बढ़ गई है कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कांग्रेस की शरण में हैं। विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच ममता दिल्ली में दो बार सोनिया गांधी से मिल चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया तो यह जा रहा है कि भेंट-मुलाकात का यह सिलसिला विपक्षी दलों को और मजबूत करने की कोशिश भर है लेकिन सियासी गलियारे में यह चर्चा आम है कि अब तृणमूल और कांग्रेस एक होने जा रही हैं।

दरअसल यह महज संयोग ही है कि जब विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुटता की पटकथा लिख रहा था तभी क्षेत्रीय क्षत्रप ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ गई। तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायक और 28 में से 20 तृणमूल सांसद बागी हो गए। बगावती तेवर अख्तियार करने वाली कोकिला घोष साफ कर चुकी हैं कि उनके साथ 20 तृणमूल सांसद भाजपा-एनडीए का साथ देंगे। तृणमूल के इन बागी विधायकों-सांसदों पर दल-बदल कानून की तलवार का भी डर नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल भी महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर चल पड़ा है।

पश्चिम बंगाल की तरह ही महाराष्ट्र में शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ी और अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और शिवसेना दो फाड़ हो गई। अदालत और चुनाव आयोग की लड़ाई के बाद असली एनसीपी अजित पवार और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे साबित हो गए।

ऐसा नहीं कि बगावत के ऐसे किस्से सिर्फ क्षेत्रीय दलों में ही हैं। 1995 में गुजरात में भाजपा को भी शंकर सिंह वघेला से ऐसी ही बगावत का सामना करना पड़ा था, तो 1969 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस टूट गई। मध्यप्रदेश में कमलनाथ को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए तो राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट। आम आदमी पार्टी भी राघव चड्ढा की बगावत के बाद पंजाब में सियासी संकट के दौर से गुजर रही है। केजरीवाल दिल्ली का राजपाट गंवा चुके हैं। ममता बंगाल हार चुकी हैं।

तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बेदखल है, तो केरल में वाम दल का आखिरी किला ढह चुका है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता की पहल मजबूरी भी है और जरूरी भी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब साझा विपक्षी इंडिया गठबंधन की सुगबुगाहट हुई तो नीतीश कुमार ने बढ़-चढ़कर अगुवाई की । 8 फरवरी 2023 को इंडिया गठबंधन ने आकार तो ले लिया लेकिन सूत्रधार नीतीश को इसका संयोजक नहीं बनाया गया । अंततः नीतीश ने कदम पीछे खींच लिए और वापस एनडीए के साथ चले गए । इधर इंडिया गठबंधन में सभी की अपनी डफली-अपना राग का सिलसिला जारी रहा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2023 से अब तक के हुए चुनावों में कहीं भी विपक्ष एकजुट नहीं दिखा और बारी-बारी से दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल के विधानसभा चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

अब जब विपक्ष ने फिर से एकजुट होने की ठानी है, तभी इंडिया गठबंधन की ताजा बैठक से आम आदमी पार्टी और द्रमुक ने दूरी बना ली। शुरू में इंडिया गठबंधन में 26 दल थे, जो घटकर 23 हो गए हैं। जदयू पहले से अलग है और आप, द्रमुक ने अब अलग राह पकड़ रखी है। इंडिया गठबंधन बने तीन साल तीन महीने बीत गए लेकिन आज तक संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। अभी भी इन दलों को जुटाने-मिलाने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भूमिका ही रहती है । करीब दस महीने बाद इंडिया गठबंधन के जुटे नेताओं में गिले-शिकवे का दौर ज्यादा रहा। हालांकि, दिल्ली अभी दूर है। लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे। उससे पहले सबसे बड़ा चुनाव यूपी का अगले साल 2027 में होने वाला है। यूं भी दिल्ली की राह यूपी से होकर गुजरती है। इससे पहले संसद का मानसून सत्र अब आने ही वाला है।

विपक्षी फूट से संसद के मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष की स्थिति और मजबूत होती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में भी मध्यप्रदेश और झारखंड में विपक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता की परीक्षा की घड़ी बार-बार आने वाली है लेकिन उससे ज्यादा चुनौती है विपक्षी दलों को अपने-अपने दलों के भीतर उपज रहे असंतोष और बगावत को थामने की।

केजरीवाल और ममता की मिसाल सामने है। यदि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन न होता तो शायद कांग्रेस को वहां भी नाटक का सामना करना पड़ता। ऐसे में यदि दलों के भीतर दिल ही नहीं मिलेंगे तो कमजोर कड़ियों को जोड़कर मजबूत विपक्षी किले के सपने भला कैसे साकार हो सकेंगे, ताश के पत्तों की तरह भरभराकर बिखरने का डर तो बना रहेगा। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की चुनौती जितनी बाहर है, उतनी ही अंदर भी।

मीनाक्षी नटराजन के पास चुनाव याचिका का विकल्प?

सौरभ वार्ष्णेय

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत न मिलने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उनके पास अब भी कोई कानूनी विकल्प बचा है। इसका उत्तर है—हाँ, चुनाव याचिका का विकल्प अभी भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 स्पष्ट करता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालतें सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। चुनाव की वैधता को चुनौती देने का उचित माध्यम चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव याचिका होती है। इसी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप से इनकार किया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मामला केवल एक उम्मीदवार के नामांकन का नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रश्न बना रही है, जबकि चुनाव आयोग और सत्तापक्ष इसे चुनावी नियमों के पालन का मामला बता रहे हैं। यदि मीनाक्षी नटराजन चुनाव याचिका दायर करती हैं और अदालत यह पाती है कि नामांकन निरस्त करने में कानूनी त्रुटि हुई थी, तो इससे चुनाव परिणाम और निर्वाचन प्रक्रिया दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश यह भी है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। चुनाव याचिका का प्रावधान इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ताकि चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो और साथ ही किसी भी कथित अन्याय की न्यायिक समीक्षा भी संभव रहे। कांग्रेस के लिए यह मामला राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। यदि चुनाव याचिका दाखिल होती है, तो यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत विश्वसनीयता पर भी व्यापक बहस को जन्म दे सकती है। दूसरी ओर, यदि न्यायालय चुनाव आयोग के निर्णय को सही ठहराता है, तो यह चुनावी नियमों के कठोर अनुपालन का एक महत्वपूर्ण

उदाहरण माना जाएगा। मीनाक्षी नटराजन के पास चुनाव याचिका का रास्ता मौजूद है, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह यह साबित कर पाती हैं या नहीं कि उनका नामांकन कानून के विपरीत या मनमाने ढंग से निरस्त किया गया था। यही कारण है कि यह मामला आने वाले समय में भारतीय चुनावी न्यायशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कसौटी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में दखल देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जस्टिस पीके मिश्र और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खारिज होने को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार जब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया जाता है, तो इसके समाधान के लिए केवल चुनाव आयोग के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, निर्णय चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, एक बार नामांकन खारिज हो जाने के बाद, इसका उपाय आमतौर पर कहीं और होता है। क्या इस न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय है जहां हमने इस स्तर पर हस्तक्षेप किया हो? सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में स्पष्ट कर दिया कि चुनाव से जुड़े मामलों पर रिट याचिका के माध्यम से कोई राहत नहीं दी जा सकती। सिर्फ सांविधानिक मामलों में ही रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। चुनाव याचिका संसदीय, विधानसभा या स्थानीय चुनावों के नतीजों की वैधता की जांच करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। आसान शब्दों में कहें तो, यह कानून के तहत किसी चुनाव में विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को अदालत में चुनौती देने का एक साधन है।

इन कारणों से अक्सर बेहोश हो जाते हैं लोग

क्या आपने कभी सोचा है कि बेहोशी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हम अपने आस - पास अक्सर ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से फिट और स्वस्थ दिख रहा है लेकिन अचानक बिना किसी कारण वो अपने बेहोश होने लगता है। बेहोशी जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है हालांकि बेहोशी के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ये कुछ कारक है जो बेहोशी के कारण हो सकते हैं-

लो ब्लडप्रेशर: बेहोशी का मेन कारण लो ब्लडप्रेशर बताया जाता है यह आमतौर पर विशेष रूप से उन लोगों को ज्यादा होता है जो 65 से अधिक आयु वर्ग के होते हैं।

निर्जलीकरण: जब आपके शरीर निर्जलित हो जाता है, आपके खून में तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है। इससे बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है।

मधुमेह: आप एक मधुमेह रोगी हैं तो आपके बेहोश होने के चांसेज ज्यादा हैं क्योंकि डायबेटिक होने पर आपको यूरिन ज्यादा आएगा जिससे आपको निर्जलीकरण होने का खतरा ज्यादा बना रहता है।

दिल की बीमारी: दिल की बीमारी भी बेहोश होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर आपके दिमाग को होने वाली खून की सप्लाई बाधित हो जाती है। बेहोशी के इस प्रकार के लिए मेडिकल टर्मेनोलॉजी में कार्डियक सिंनकॉप कहा जाता है।

स्वास्थ्य के लिए वरदान है प्याज

प्याज एक अत्यंत गुणकारी पौधा है जिसमें औषधीय गुण भी पाएं जाते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लूकोस भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हरा प्याज चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके इलावा मसूड़े में सूजन और दांत में दर्द होने पर प्याज के रस और नमक का मिश्रण लगाने से दर्द में राहत मिलती है।

पेट के लिए वरदान पपीता

फलों में पपीता पेट के लिए काफी लाभदायक है। इसमें पेप्सिन नामक तत्व पाया जाता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। पपीते का सेवन रोज करने से पपीते में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। इसमें न सिर्फ बीटा कैरोटिन, बल्कि लाइकोपिन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। जो पुरुष ज्यादा लाइकोपिन युक्त फल और सब्जियों का सेवन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर की आशंका 82 प्रतिशत कम होती है।

डिमेंशिया के खतरे को कम करती है नियमित कसरत

नियमित रूप से कसरत करने के कई फायदे होते हैं। इससे शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने में मदद तो मिलती ही है। एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में भी यह योगदान करता है। नियमित रूप से कसरत करने से न केवल हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है बल्कि डिमेंशिया जैसी भूलने वाली बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। चूहे पर किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया कि कसरत शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन की उत्पादकता बढ़ा सकता है। यह प्रोटीन मस्तिष्क को सक्रिय करने के साथ ही (न्यूरो) तंत्रिका से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है। अध्ययन में पाया गया कि चूहे के नियमित कसरत के दौरान कुछ रसायन स्वतः मस्तिष्क में जमा हुए और मस्तिष्क के लिए बीडीएनएफ (मिरेकल-ग्रो) का उत्पादन करने लगे। बीडीएनएफ याददाश्त बढ़ाने और तंत्रिका कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। स्तनधारियों में कसरत से बढ़ने वाले बीडीएनएफ के पीछे होने वाली जैविक प्रक्रिया को हमारा यह अध्ययन दर्शाता है।

दिमाग तेज करने इस्तेमाल करें ये जड़ी-बूटियां

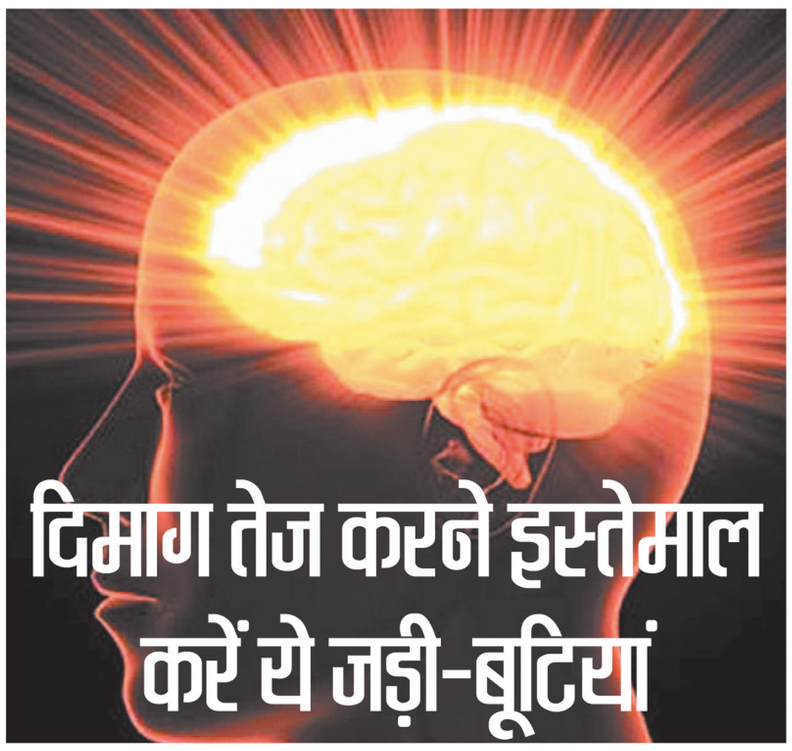

आज हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो ताकि वे हर जगह अपनी अलग पहचान बना सके। क्योंकि दिमाग हमारे शरीर को वो हिस्सा है जिसके संकेत के बिना शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर सकता। लेकिन कई बार बढ़ती उम्र, गलत आदतों, नशे और आवश्यक पोषक तत्वो की कमी आदि से याददाश्त कमजोर होने लगती है।

ऐसी कौन सी जड़ी-बूटियां है जिनको अपने आहार में शामिल करके आप आसानी से तेज दिमाग पा सकते हैं।

जटामांसी

जटामांसी औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है। यह दिमाग के लिए एक रामबाण औषधि है। यह याददाश्त को तेज करने की भी अचूक दवा है। एक चम्मच जटामासी को एक कप दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है।

बाह्मी

जड़ी-बूटी को दिमाग के लिए टॉनिक भी कहा जाता है। यह दिमाग को शांति प्रदान करती है और याद्दाश्त को मजबूत करने में भी मदद करती है। आधे चम्मच बाह्मी के पाउडर और शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है।

शंख पुष्पी

शंख पुष्पी दिमाग को बड़ाने के साथ-साथ हमारी याद करने की क्षमता और सीखने की क्षमता को भी बड़ाती है। दिमाग को तेज करने के लिए आधे चम्मच शंख पुष्पी को एक कप गरम पानी में मिला कर लें।

दालचीनी

दालचीनी सिर्फ गर्म मसाला ही नहीं, बल्कि एक जड़ी-बूटी भी है। यह दिमाग को तेज करने की बहुत अच्छी दवा है। रात को सोते समय नियमित रूप से एक चुटकी दालचीनी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर लेने से डिप्रेशन में राहत मिलती है और दिमाग तेज होता है।

हल्दी

यह सिर्फ खाने के स्वाद और रंग में ही इजाफा नहीं करती है, बल्कि दिमाग को भी स्वस्थ रखने में मदद करती है। हल्दी दिमाग के लिए बहुत अच्छी जड़ी-बूटी है। इसके नियमित सेवन से एल्जाइमर रोग नहीं होता है। एक शोध के अनुसार, हल्दी में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कुरकुमीन दिमाग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है

जायफल

गर्म तासीर वाले जायफल की थोड़ी मात्रा का सेवन करने से दिमाग तेज होता है। इसको खाने से आपको कभी एल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी नहीं होती।

अजवाइन की पत्तियां

अजवाइन में भरपूर मात्रा में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। खाने में सुगंध के अलावा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है।

तुलसी

तुलसी कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए एक जानी-मानी जड़ी बूटी है। इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हृदय और दिमाग में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है। साथ ही इसमें पाई जाने वाली एंटी-इंफ्लेमेटरी अल्जाइमर जैसे रोग से सुरक्षा प्रदान करता हैं।

केसर

केसर का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ अनिद्रा और डिप्रेशन दूर करने वाली दवाओं में किया जाता है। इसके सेवन से दिमाग तेज होता है।

कालीमिर्च

दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काली मिर्च का उपयोग करें। काली मिर्च में पाया जाने वाला पेपरिन नामक रसायन शरीर और दिमाग की कोशिकाओं को आराम देता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी यह रसायन जादू सा काम करता है।

अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो जरूर खाएं मक्खन

मक्खन हर घर मे पाया जाता है। इसे उपयोग हम खाने में करते है। इसमें कैलोरिज की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इसे हर रोज खाया जाए तो इसे आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है। पर इसके बहुत से ऐसे गुण शामिल है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में मौजूद है इसलिए यह छोटे बच्चों के बढ़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको लिवर संबंधी समस्या होती है, उनके लिए बटर में पका खाना सुपाच्य होता है। आज हम आपको मक्खन से सेहत के लिए फायदों के बारे में बताएगे।

अच्छा मूड : मक्खन में अधिक मात्रा में सेलेनियम होता है, जिससे खाने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है। जब हम इसे गरमा-गरम सब्जी में डाल कर खाते है तो इसे खाते ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है और सब्जी खाने में स्वाद भी लगती है।

थायराइड: मक्खन थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती हैं। अगर आप सोचते है कि इसे खाने से आपका वजन बढ जाएगा तो ऐसी नही है।

दिमागी विकास: मक्खन खाने से बच्चों का दिमागी विकास अच्छा रहता है और आंखो की रौशनी ठीक रहती है। इसीलिए अपने बच्चों को खाने में दूध और मक्खन जरूर दें।

एनर्जी लेवल बढाए : बटर को खाने के बाद हमारे शरीर में फैट में परिवर्तित हो जाता है और जरुर पड़ने पर यह हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता हैं।

कैंसर और ट्यूमर : मक्खन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है और यह हमें कैंसर या ट्यूमर बचाता है। इसका प्रयोग एंटी एजिंग क्रीम में भी किया जाता है।

त्वचा में चमक : मक्खन को चेहरे पर लगाने से त्वचा कोमल बनती है और चेहरे में निखार आता है।

बटर खाने से अच्छी नींद आती है: जब भी आपके काम करने के बाद में थकावट होती है तो ऐसे में रात के खाने में बटर जरुर खाएं। इसे खाने से अच्छी नींद आती है क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है।

विटामिन डी : मक्खन में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा पाई जाती हैं इसीलिए इसे नाश्ते में नही खाना चाहिए। मक्खन को चेहरे पर लगाने से त्वचा कोमल बनती है और चेहरे में निखार आता है।

सोते समय शरीर के साथ क्या होता है?

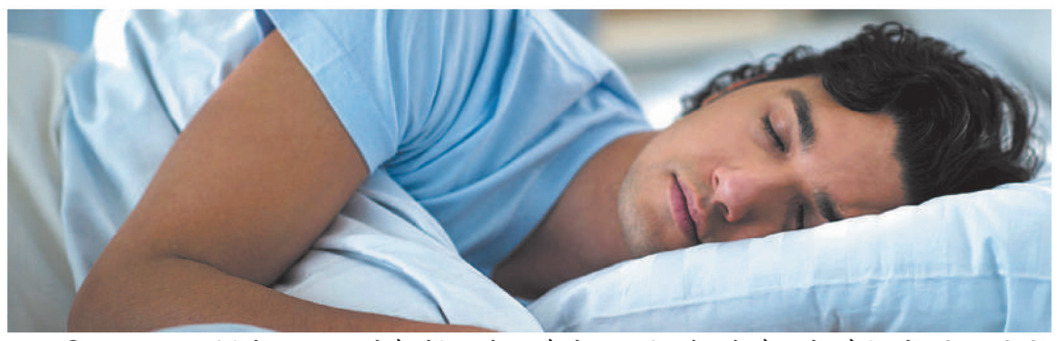

हम बिना कुछ खाए कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन सोए बिना दो दिन रह पाना भी भारी पड़ सकता है। यकीनन हमारे शरीर और दिमाग के लिए सोना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सोने से शरीर को आराम मिल मिलता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हम फिर से ऊर्जावान बन पाते हैं। यही कारण है कि जब हम सोकर उठते हैं तो खुद को रिफ्रेश महसूस करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मर जाने के बाद हम दरअसल सोए हुए ही होते हैं। खैर ये कितना सच है ये तो हम नहीं जानते लेकिन सोने के बाद हमारे शरीर के साथ कई अजीब चीजें होती हैं, जिनके बारे शायद आप अभी न जानते हों। तो चलिए जानें कि सोने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या अजीब चीजें होती हैं।

शरीर का तापमान हो जाता है कम

आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो लेकिन रात में सोने के दौरान शरीर का तापमान गिर जाता है। ऐसा प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि जब आपका शरीर सोने के लिए तैयार होता है जिसके लिए दिमाग मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। शरीर का सबसे कम तापमान रात को तकरीबन 2 बजे होता है, इसी वजह से अक्सर आपको रात को इस समय के आस-पास कम्बल ढूंढने की जरूरत पड़ती है।

कुछ देर के लिए हो जाते हैं लकवाग्रस्त

जब हम नींद में होते हैं तो कुछ समय के लिए हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहां है, क्या कर रहे हैं और खुद से पूरी तरह काबू खो देते हैं, जब तक कि आपकी नींद नहीं टूट जाती है। ऐसा अक्सर बुरे सपनों में होता है। ऐसी विवशता अक्सर सोने के दौरान होती है। ऐसा आरईएम फेज के दौरान होता है जिसमें शरीर, गहरी नींद में चला जाता है।

गिरने का अहसास होता है, आंखें घूमती हैं

नींद में अक्सर जब तक कि कोई आपको जगा न दें या आपकी नींद न टूट जाएं, हमें ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं। इसे हाईपनोटिक पल्स कहते हैं। हर किसी को कभी न कभी इसका अहसास होता ही है। कई बार तो सोने के तुरंत बाद लगता है कि हम बेड से गिरने वाले हैं। वहीं रिफ्रेश होने के बाद भी अगर कोई सोता है तो आंखों का मूवमेंट शुरू हो जाता है।

शरीर में लगता है झटका

कई बार हम को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही हम सोने वाले होते हैं, तो शरीर में झटका लगता है और नींद खुल सी जाती है। 70 प्रतिशत लोगों को सोते वक्त ऐसा महसूस होता है। इसे हाईपेनिक जर्क कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा चिंता या तनाव के कारण होता है जो शारीरिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। कुछ लोगों में कई बार सोते हुए पेट फूलने की समस्या भी हो जाती है। रात में सोने के दौरान, शरीर भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लगा होता है, ऐसे में गैस बनने की समस्या होती है लेकिन वह रिलीज नहीं हो पाती है। इस कारण, पेट फूल जाता है। लेकिन ऐसे में गैस निकलने पर आपको और बाकी लोगों को पता नहीं चलता है।

ब्रश करना है जरूरी

सुबह बिस्तर छोड़ते ही हमारा सबसे पहला काम ब्रश करना ही होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दांतों की सफाई व ताजगी के लिए ब्रश करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दांतों की रोज दिन में दो बार सफाई करना बेहद जरूरी है। दांतों की सफाई करने से सांसों की तकलीफ व मुंह की अन्य बीमारियां नहीं होतीं। इसके साथ ही एक हालिया शोध कहता है कि याद्दाश्त को दुरुस्त रखने में भी दांतों की सफाई जरूरी है। हाल में किए एक शोध में बताया गया है कि वयस्कों द्वारा अपने दांतों की उचित देखभाल करना यानी नियमित रूप से ब्रश करना याददाश्त बनाए रखने में मददगार साबित होता है।

क्या कहता है शोध?

पहले के शोधों में भी दांतों की साफ-सफाई न रखने को डिमेंशिया (याददाश्त कम होना) समेत हृदयरोग, स्ट्रोक व डायबिटीज के लिए जिम्मेदार बताया गया था। न्यूयार्क के कोलंबिया कालेज के शोधकर्ताओं के मुताबिक मसूढ़ों की बीमारी मस्तिष्क की क्रियाविधि को प्रभावित करने के साथ पूरे शरीर में जलन पैदा करती है। शोध में 60 साल व उससे ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया। जिन लोगों में मसूढ़ों की बीमारी के लिए जिम्मेदार पैथोजन ज्यादा पाया गया उनमें याददाश्त संबंधी दिक्कतें देखी गईं। शोधकर्ता ने बताया कि जिन लोगों में पैथोजन का उच्च स्तर पाया गया उनमें याददाश्त की गंभीर परेशानी देखी गई। शोध से साफ है कि दांतों-मसूढ़ों की उचित देखभाल न करने से डिमेंशिया का खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2400 पुरुषों व महिलाओं पर किए गए शोध में दांतों की बीमारियों को याददाश्त पर प्रभाव डालने वाला पाया गया। दांतों की बीमारी से पीड़ित 5.7 फीसदी लोगों को याददाश्त की सामान्य समस्या देखी गई जबकि 6.5 फीसदी लोगों को री-काल (दोबारा याद करना) व 22.1 फीसदी लोगों में लगातार भूलने की परेशानी देखी गई।

रेसिपी

टोर्टीला

सामग्री

1 कप मकई का आटा
1/4 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर
1/4 टी-स्पून अजवायन , ऐच्छिक
2 टी-स्पून तेल
नमक स्वादअनुसार
1/4 टी-स्पून तेल , आटा गूंथने के लिए
मकई का आटा , बेलने के लिए

विधि

मकई का आटा, लाल मिर्च पाउडर, अजवायन, 1 टी-स्पून तेल और नमक को एक बाउल में मिलाकर, गरम पानी का प्रयोग कर नरम आटा गूंथ लें। 10 मिनट के लिए रख दें। बचे हुए 1 टी-स्पून तेल का प्रयोग कर दुबारा गूंथ लें। 4 बराबर भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 2 प्लास्टिक शीट के बीच रखकर, 250मि.मी। (10) व्यास के गोल आकार में बेल लें। टोर्टीला को आसानी से बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा छिड़कें। एक तवा या कढ़ाई को उलटा रखकर गरम करें और गरम होने पर, हल्के हाथों से रोटी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि किनारे मूड़ ना जाए ऊपरी परत पर छोटे दाग आने तक पका लें। रोटी को पलट कर और कुछ सेकेन्ड तक पका लें। बचे हुए आटे का प्रयोग कर 3 और रोटी बनाएं।

पनीर समोसा

सामग्री

8 समोसा पट्टियां , **भरावन मिश्रण के लिए:** 1 टेबल-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1/4 कप बहुत बारीक कटे प्याज, 1 टी-स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 कप बहुत बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 1/2 टी-स्पून अमचूर पाउडर, 1 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 कप बहुत बारीक कटा पनीर, नमक , स्वाद अनुसार, 2 टेबल-स्पून बारीक कटा हरा धनिया, **परोसने के लिए:** पुदीना चटनी

विधि

भरावन मिश्रण के लिए: एक चौड़े पैन में तेल गरम कीजिए। जीरा डालिए। जब ज़ीरा चटकने लगे तो प्याज और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर 2 मिनट तक भूनिए। शिमला मिर्च, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पनीर, नमक तथा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मध्यम आंच पर और 2 मिनट भूनिए। पूरी तरह ठंडा कीजिए और मिश्रण को बराबर 8 भागो में बांटकर एक तरफ रख दीजिए।

कैसे आगे बढ़े: समोसा पट्टी को सूखी, साफ, समतल जगह पर रखिए। पट्टी के एक कोने पर 1 भाग भरावन मिश्रण रखिए और तीकोण के रूप में मोड़िए। किनारों पर थोडा पानी लगाकर समोसे को बंद कर दीजिए। (नीचे दिए गए चित्रों की सहायता लीजिए)। शेष बची सामग्री और पट्टियों से यही प्रक्रिया दोहराते हुए बाकी 7 समोसे बनाइए। एक कड़ाही में तेल गरम कीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके समोसों को चारों तरफ से भूरा होने तक तल लीजिए। तेल सोखनेवाले कागज पर निकालिए और पुदीना चटनी के साथ गरमा गरम परोसिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी त्यागी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन रद्द होने के मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि इन सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं ने मामले में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई हैं। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज की थी। इसके बाद शनिवार को प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने पूरे प्रकरण को सीधे-सीधे सत्ता हथियाने की चाल बताया। वह यहीं नहीं रुकीं, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर उंगली उठाकर कहा, सबसे खराब बात ये है कि चुनाव आयोग और पूरे सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारियों का त्याग किया है। इतना ही नहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर तीखे सवाल उठा दिए।

अमित शाह का मेट्रो शहर की जनसांख्यिकी पर बड़ा निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जनसांख्यिकीय बदलावों पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित आयोग को सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों में जनसंख्या परिवर्तन का गहन अध्ययन करने और आकलन प्रस्तुत करने को कहा है। यह कदम देश की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण होगा। इसके पहले, 5 जून को केंद्रीय मंत्री शाह ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों में किसी भी जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यह निर्देश उन प्रयासों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

अमेरिकी हमलों में भारतीयों की मौतः स्वामी ने उठाए सवाल

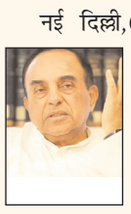

नई दिल्ली,(ईएमएस)। हिंदू राष्ट्रवादी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा तीन भारतीय नाविकों की हत्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रीढ़ की हड्डी बची है, तब उन्हें सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन करके विरोध जताना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को तलब करने के बाद की।

बीजेपी नेता स्वामी ने विदेश मंत्रालय के अमेरिकी दूतावास से बात करने पर सवाल उठाकर स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि, मुझे पता है कि मोदी ऐसा क्यों नहीं करने वाले है। भारत ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को दो बार तलब किया, और कहा कि भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी सेना के घातक और जानलेवा हमले अस्वीकार्य हैं।

भारत अपनी आत्मा खो रहा है शशि थरूर का आत्ममंथन

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देश में बढ़ते भेदभाव और विभाजनकारी माहौल पर गहरा दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता थरूर ने लिखा कि जब किसी देश को धीरे-धीरे अपनी आत्मा खोते हुए महसूस किया जाता है, तब एक गहरा और टीस भरा दुख होता है। जो लोग भारत को अनेकता में एकता के शानदार समावेशी प्रयोग के तौर पर देखते आए हैं, उन्हें हाल के वर्षों में निराशा मिली है। उनका मानना है कि कभी-कभी कोई एक घटना रोजमर्रा की राजनीति के शोर-शराबे को चीरकर हमारे नैतिक पतन की गहराई को उजागर करती है। ऐसी ही एक घटना हाल ही में सामने आई, जिसकी हेडलाइन थी कि होटल से बाहर निकाला गया अल्पसंख्यक बीजेपी नेता। यह घटना सज्जाद यूसुफ शाह से जुड़ी है, जो भाजपा के जम्मू-कश्मीर मीडिया सह-प्रभारी हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यात्रा के दौरान बीजेपी नेता शाह को होटल से यह कहकर जाने को कहा गया कि उनकी मुस्लिम और कश्मीरी पहचान समस्याग्रस्त है।

दिल्ली दंगाः शरजील इमाम ने फिर मांगी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा अदालत में नई जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगकर अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की है। शरजील इमाम ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वह पिछले करीब छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी पिछली जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जनवरी, 2024 को खारिज करने के बाद से मुकदमे की सुनवाई में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इमाम की जमानत याचिका को अस्वीकार किया था। उस फैसले के बाद अब उन्होंने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसमें लंबी अवधि की हिरासत और मुकदमे में हो रही देरी को जमानत का मुख्य आधार बनाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पुलिस के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत 4 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगी।

सरकार के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का बड़ा बयान

युवाओं के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा भारत

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को देश के युवाओं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के विजन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार %युवाओं के नेतृत्व वाले विकास% (ङ्मह्वह्लद्ध-द्यद्गस्र ष्ठद्ग1द्गद्यश्चद्वद्गठ्ठह्ल) की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने %पिछले 12 वर्षों% को भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास में आए क्रांतिकारी बदलाव का दौर बताया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के साथ ही देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत के युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विनिर्माण, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि भारत के युवा उन क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं जो देश और दुनिया के भविष्य को आकार देंगे।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''राजग सरकार युवाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। पिछले 12 वर्षों की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि भारत के युवाओं का अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रति आत्मविश्वास बढ़ा है।'' मोदी सरकार के सत्ता में 12 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों से एक ऐसा परिवेश बना है जो नवोन्मेष, उद्यमिता और उद्यम को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा, ''आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में से एक है और इनमें से कई सफलता की कहानियां हमारी युवा शक्ति लिख रही है और वह भी छोटे कस्बों और गांवों से।'' मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं ने खेल और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है और युवा भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार देश का मान बढ़ाया है।

उन्होंने कहा, ''साथ ही, खेलों का मजबूत माहौल, बेहतर बुनियादी ढांचा और खिलाड़ियों को ज्यादा समर्थन मिलने से युवा प्रतिभाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा मिल रहा है।'' मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वह आजादी के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को शुरू हुआ।

मोदी ने 2024 के संसदीय चुनाव में एक और जीत के बाद नौ जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस साल 10 जून को मोदी ने 1952 के आम चुनाव के बाद निर्वाचित देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वर्ष 1947 से 1952 तक नेहरू का कार्यकाल एक अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर था क्योंकि आजादी के बाद 1952 तक चुनाव नहीं हुए थे।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का यू-टर्न

अभिषेक संग सुलह, एनडीए के खिलाफ जंग का ऐलान!

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस में चल रही बगावत के बीच, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का समर्थन किया है और काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी सांसदों के गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को पहले भ्रष्ट कहने के बाद अब उनके साथ सुलह का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभिषेक को बड़ा होते देखा है। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे बातें कह सकता हूँ, इसलिए ठीक है। अब हमें एनडीए के ख़िलाफ़ लड़ना है।

अभिषेक बनर्जी पर अपनी टिप्पणी के बारे में कल्याण बनर्जी ने कहा कि वह मेरे बेटे की तरह हैं। बेटे की गलतियों को माफ करना पिता का काम है। देश में लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाए। यह मुख्यमंत्री प्रतिशोध की भावना रखने वाली हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। टीएमसी और कांग्रेस के विलय की अटकलों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ विलय नहीं कर रहे हैं।

बागी सांसदों पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दें। उन्हें भाजपा की शरण में ही रहना होगा। यह सब एक चाल है।

वे अपने चुनाव क्षेत्रों के विकास का हवाला देते हैं, लेकिन जो लोग अपने चुनाव क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते, वे क्या काम करेंगे? जब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। सीएम के साथ बातचीत के बाद भी पिछले एक महीने में क्या विकास हुआ है? भाजपा हमें परेशान कर रही है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। पश्चिम बंगाल में किसी भी विपक्ष को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जैसी हम कर रहे हैं। जो 19 सांसद भाजपा में जा रहे हैं, उन्हें भाजपा स्वीकार नहीं करेगी।

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी और पार्टी के अहम नेताओं में से एक, कल्याण बनर्जी ने बगावती तेवर अपनाते हुए ममता के भतीजे अभिषेक पर पार्टी को बर्बाद करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। टीएमसी सांसद ने ममता बनर्जी को यह अल्टीमेटम भी दिया कि वे या तो उन्हें चुनें या अभिषेक बनर्जी को, जिससे पार्टी के भीतर सत्ता के अलग-अलग केंद्रों के बीच संबंधों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

अमरनाथ यात्रा : अमित शाह ने की सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा

- बनाया गया अभेद्य सुरक्षा घेरा, घाटी से लेकर पहाड़ों तक हाई अलर्ट

नईदिल्ली। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार इस बार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सभी सुरक्षा और नागरिक एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि विभागीय तालमेल में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस बार यात्रा केवल पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक, त्वरित खुफिया समन्वय और जमीनी निगरानी के संयुक्त ढांचे पर आधारित होगी।

बैठक में सबसे अधिक जोर बहुस्तरीय अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार करने पर दिया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय बलों, सेना और विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयों को एकीकृत अभियान प्रणाली के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्गों, आधार शिविरों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती होगी। चौबीसों घंटे गश्त, कड़ी वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष नियंत्रण प्रणाली विकसित की जा रही है। उद्देश्य साफ है कि किसी भी खतरे को जन्म लेने से पहले ही कुचल देना।

तकनीकी निगरानी इस बार सुरक्षा रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बनने जा रही है। यात्रा मार्गों और शिविरों पर व्यापक स्तर पर कैमरा नेटवर्क लगाया जाएगा। ड्रोन के जरिये ऊंचाई वाले कठिन इलाकों, संकरे मार्गों और संवेदनशील बिंदुओं पर लगातार नजर रखी जाएगी। नियंत्रण कक्षों को लाइव वीडियो फीड मिलेगी, जिससे किसी भी संदिग्ध हलचल या आपात स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझा करने के लिए विशेष संचार प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

जमीनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे यात्रा मार्गों और प्रमुख शिविरों पर तैनात रहने का फैसला लिया गया है। ये अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन अभ्यास और यात्री सहायता केंद्रों की निगरानी करेंगे। सरकार का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व की सीधी मौजूदगी से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और किसी भी संकट की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।

हालांकि सरकार का फोकस केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्वच्छ पेयजल, अस्थायी आवास, बिजली और साफ सफाई की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऊंचाई वाले कठिन मार्गों को देखते हुए विशेष चिकित्सकीय शिविर लगाए जाएंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

पीवी सिंधु का ऑस्ट्रेलियन ओपन का सफर खत्म

सिडनी। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु की 2026 सीज़न में अपना पहला बड़ा ख़िताब जीतने की कोशिश जारी रही, लेकिन शनिवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सेमीफ़ाइनल में उन्हें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में 43 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी को दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी यामागुची से 22-20, 21-12 से हार का सामना करना पड़ा। यह 2026 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर सिंधु का दूसरा सेमीफ़ाइनल था। इससे पहले, वह जनवरी में मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफ़ाइनल तक पहुँची थीं, जहाँ उन्हें चीन की वांग झियी ने हराया था। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट का बीडब्ल्यूएफ सर्किट पर सबसे हालिया खिताब 2024 में लखनऊ में हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल में आया। कांटे की टक्कर वाले शुरुआती गेम में सिंधु ने मज़बूत शुरुआत की और मिड-गेम ब्रेक तक थोड़ी बढ़त बनाए रखी। ब्रेक के बाद यामागुची ने लगातार छह पॉइंट जीतकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली, लेकिन सिंधु ने वापसी करते हुए फिर से मोमेंटम हासिल किया और एक बार फिर आगे निकल गईं।

मैच आखिरी क्षण तक रोमांचक बना रहा, सिंधु ने 20-19 पर मैच प्वाइंट बचाया, लेकिन अंततः पहला सेट गंवा दिया। दूसरे सेट में यामागुची ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और लगातार सात प्वाइंट जीतकर 13-6 की बढ़त हासिल कर ली और मैच पर अपना नियंत्रण बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। इस हार के साथ ही सिंधु का टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन से सभी भारतीय खिलाड़ी बाहर हो गए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

एनबीएफसी का बहीखाता वित्तवर्ष 28 तक 93 लाख करोड़ रू. पहुंचने का अनुमान

नईदिल्ली। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का बहीखाता वित्त वर्ष 2027-28 के अंत में 92.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2028 के बीच एनबीएफसी का बहीखाता 16 प्रतिशत बढ़ जाएगा। मगर रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना रेहन के कर्ज और ग्रामीण कर्ज में आगे चलकर परेशानी भी बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र में कुल 61.1 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां थीं और 2027-28 तक बहीखाते में सालाना 15 प्रतिशत वृद्धि होते रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'एनबीएफसी के बहीखाते को अब तक खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) तथा सेवा क्षेत्र में ऋण की अधिक मांग से काफी मदद मिली है।'

भारत की रक्षा प्रणाली में 2 दिनों में 3 सफल टेस्ट!

नईदिल्ली। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा महाशक्तियों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और एंटी-शिप खतरों को हवा में ही नेस्तनाबूद करने की अचूक मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा प्रणाली है। भारत ने महज दो दिनों के भीतर लगातार तीन सफल उड़ान परीक्षण कर अपनी इस आसमानी दीवार की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों की मौजूदगी में 10 और 11 जून को किए गए इन परीक्षणों की सफलता भारत की रक्षा क्षमताओं को और मज़बूत करेगी, क्योंकि अब देश के पास मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है।

15 साल तक किया निवेश मिला लाखों का रिटर्न

नईदिल्ली। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड लगातार आकर्षक विकल्प बने हुए हैं। खासकर सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए नियमित निवेश करने वालों के लिए लंबे समय तक संपत्ति बनाने का मजबूत माध्यम साबित हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की कई इक्विटी स्कीमों ने बीते 15 सालों में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को 15 से 18.5 फीसदी तक सालाना का रिटर्न दिया है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कीमों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड शामिल है। लगभग 7,789 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले इस फंड ने 15 सालों में 18.50% का CAGR रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 5 हजार रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो उसका निवेश बढ़कर 48.41 लाख रुपए हो जाता।

कई शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम

नईदिल्ली। शनिवार को सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें जारी कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के भाव 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचने के बाद तेल की कीमतों में भी बदलाव आया है। आज कई शहरों में तेल के दाम बदल गए हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे देश के चारों महानगरों में तेल कीमतें स्थिर हैं। तेल कंपनियों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल 22 पैसे महंगा होकर 101.92 रुपए लीटर हो गया है तो डीजल 21 पैसे बढ़त के साथ 95.37 रुपए लीटर पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल 11 पैसे महंगा होकर 113.65 रुपए लीटर हो गया तो डीजल 14 पैसे महंगा होकर 99.36 रुपए लीटर बिक रहा है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 16 पैसे सस्ता हो गया है।

भारत में निवेश की सुस्ती गहरे संरचनात्मक बदलावों का नतीजा

आर कविता राव

पश्चिम एशिया संकट और उसके कारण कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को लगा आपूर्ति झटका बताता है कि भारत एक आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। उभरते जोखिमों को दो घटकों में बांट कर देखा जा सकता है: उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कच्चे माल की कम उपलब्धता के कारण जरूरी चीजों की कमी और मजबूत अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून विपरीत रहने वाला है।

विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं जिसके चलते देश में शुद्ध पूंजी की आवक कम हो रही है। भुगतान संतुलन की चुनौतियां व्याप्त हैं और विनिमय दर पर दबाव उत्पन्न हुआ है। निजी कारोबारी क्षेत्र की ओर से धीमे निवेश की समस्या पहले से व्याप्त है। इस सूची में जहां दो शुरुआती घटकों पर ध्यान देने की जरूरत है वहीं देश की दीर्घकालिक वृद्धि संभावना तीसरे घटक पर कहीं अधिक निर्भर करती है।

पिछले दशक के दौरान कई अहम नीतिगत और नियामकीय बदलाव हुए। इनमें दिवालियापन और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) का पुनर्गठन और पूंजीगत आय पर कर लगाने के तरीके में बदलाव शामिल था। इस आलेख में इनमें से कुछ बदलावों के संभावित विपरीत प्रभावों को लेकर एक वैचारिक प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। आईबीसी से शुरुआत करें तो इसे 2016 में इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ पेश किया गया था कि वित्तीय अनुशासन लाया जाए और कॉरपोरेट में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दस वर्ष बाद, इस संहिता ने कॉरपोरेट क्षेत्र में कुछ व्यवहारगत बदलावों को प्रेरित किया है।

प्रारंभिक अवधि में व्यापक स्तर पर ऋण

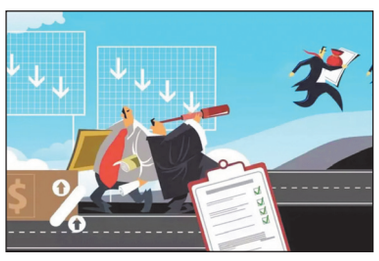

लेने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई। बदले हुए नियामक वातावरण ने कॉरपोरेट निवेश व्यवहार में बदलाव पैदा किया। निवेश को संचित आय, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और इक्विटी बाजारों से वित्तपोषित करने की कोशिश की गई। दूसरे शब्दों में कंपनियों ने संचित आय का बड़ा भंडार बनाया ताकि अनिश्चित समय में ऋण चुकाने में मदद मिले और निवेश भी किया जा सके।

विचार प्रयोगः निवेश व्यवहार में इस बदलाव के परिणाम। इक्विटी, धन के स्रोत के रूप में, ऋण की तुलना में अधिक महंगी होती है। इक्विटी से जुड़ा जोखिम अधिक रिटर्न की मांग करता है। नियामक वातावरण में इस संरचनात्मक बदलाव के परिणामस्वरूप नए उपक्रमों पर अपेक्षित रिटर्न दर अधिक होनी चाहिए ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। क्या यह निवेश के लिए एक अवरोधक के रूप में काम कर सकता है?

दूसरा महत्त्वपूर्ण नियामक परिवर्तन बीआईटी के पुनर्गठन से संबंधित है। व्हाइट इंडस्ट्रीज और वोडाफोन जैसे कई हाई-प्रोफाइल निवेशक-राज्य विवाद में हारने के बाद, भारत ने 2016 में लगभग 75 बीआईटी को एकतरफा रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद आया 2016 मॉडल बीआईटी राज्य की संप्रभुता की ओर झुका हुआ था। इसमें निवेशकों से अपेक्षा की गई कि वे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले पांच वर्षों तक स्थानीय न्यायिक उपायों का सहारा लें।

यह तर्क दिया जा सकता है कि नियामक व्यवस्था में इस तरह का बदलाव देश में निवेश को हतोत्साहित करेगा। भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में तेज गिरावट इस कथन की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

यदि यह बदला हुआ ढांचा विदेशी निवेशकों के लिए निवेश माहौल को और खराब करता है तो सकल प्रवाह भी प्रभावित होना चाहिए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले 10 वर्षों में सकल एफडीआई प्रवाह में गिरावट केवल 2022-24 के दौरान दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 में सकल एफडीआई प्रवाह 94.53 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सतत सकल एफडीआई प्रवाह के साथ समस्या कहीं और दिखाई देती है। शुद्ध एफडीआई प्रवाह में तेज गिरावट का एक अन्य कारण भारत से बाहर प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि है।

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाएं हुई सुदृढ़: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होकर एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एनएचएम कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री साय ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में एनएचएम कर्मियों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके कार्यों का सम्मान करती है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में, जहां सड़कें और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी पैदल चलकर, नदी-नाले पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और अब तक लगभग 90 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ है। अब वहां विकास और जनकल्याण की नई संभावनाएं खुल रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में हुए व्यापक विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ी है और सभी के सहयोग से विकसित एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जशपुर से लेकर सुकमा तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ बस्तर अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं और सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगें पूरी की जा चुकी हैं तथा स्थानांतरण नीति भी जारी कर दी गई है।उन्होंने कहा कि अब एनएचएम कर्मचारी भी कैशलेस उपचार योजना के दायरे में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मियों के लिए जीवन बीमा सुविधा लागू की गई है, जिसके तहत सामान्य मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 करोड़ 40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए विशेषीकृत 116 नए स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्थानों का चयन किया जा चुका है।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा के बाद एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गजमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी तथा एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मेयर मीनल चौबे ने पंडरी कपड़ा बाजार की सफाई व्यवस्था देखी

रायपुर। नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे नगर निगम जोन 2 क्षेत्र अंतर्गत राजधानी शहर के पंडरी कपड़ा बाजार की सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण शहीद हेमू कालाणी वार्ड पार्षद कृतिका जैन और जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया की उपस्थिति में किया. महापौर ने पंडरी कपड़ा बाजार गेट नम्बर 2 के पास के मुक्कड़ की सफाई का अवलोकन किया. मुक्कड़ में भारी मात्रा में कचरा देखकर नाराजगी व्यक्त की और प्रतिदिन मुक्कड़ की नियमित सफाई करवाकर कचरा परिवहन करवाने की व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी को दिए.महापौर मीनल चौबे ने जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी को पंडरी कपड़ा बाजार की सफाई कामगार टीम में समान संख्या में महिला और पुरुष सफाई कामगारों को ड्यूटी पर रखने शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने कहा. अभी पंडरी कपड़ा बाजार क्षेत्र के सफाई गैंग में 7 महिला सफाई कामगार और 2 पुरुष सफाई कामगार ड्यूटी दे रहे हैं. महापौर ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी को पुरुष ठेका सफाई कामगारों की संख्या बढ़ाये जाने आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए. महापौर ने पंडरी कपड़ा बाजार की सफाई व्यवस्था चुस्त रखने और नागरिकों और व्यापारियों के मध्य सफाई को लेकर जनजागरण अभियान चलाने निर्देशित किया.महापौर मीनल चौबे ने जोन 2 द्वारा जोन 2 क्षेत्र में देवेन्द्र नगर नाला,नमस्ते चौक नाला, एक्सप्रेस वे नाला में बारिश पूर्व सफाई कार्य की निरीक्षण कर स्थल पर बारिश पूर्व सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और बारिश के पूर्व नालों की लचर सफाई व्यवस्था देखकर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई ठेकेदार और जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी को जमकर फटकार लगायी. महापौर ने मानसून की पहली बारिश के पूर्व सभी नालों की तल्ले तक सुव्यवस्थित सफाई करवाकर लद्दी निकालकर गंदे पानी की सुगम निकासी व्यवस्था कायम करना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई ठेकेदार को दिए हैं।

समपार फाटक जागरूकता अभियान का समापन

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर 06.06.26 से 12.06.26 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग के द्वारा समपार फाटक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत आमजन को सुरक्षित समपार फाटक पार करने के प्रति जागरूक किया गया । अंतिम दिन दिनांक 12.06.26 को संरक्षा अधिकारियों , संरक्षा सलाहकारों तथा सिविल डिफेंस वोलैंटियर के द्वारा विभिन्न समपार फाटकों जैसे उरकुरा गेट , उरकुरा पश्चिम गेट (समपार फाटक-415), खमतराई गेट , सरस्वती नगर गेट (समपार फाटक-419) तथा रायपुर एवं सरस्वती नगर स्टेशन तथा ट्रेन क्रमांक- 12536 में जाकर लोगों को पॉमप्लेट वितरण करके , स्टीकर चिपका कर एवं बैनर लगाकर लोगों को फाटक बंद होने पर उसे पार न करने की काउंसलिंग की गई तथा समपार फाटक को सही तरीके से पार करने एवं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए कुल लगभग 660 लोगों की काउंसिलिंग की गई।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता: राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमलपुर, पहाड़गांव एवं पण्डोनगर का दौरा कर ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया। डोर-टू-डोर जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा मु विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य

सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। जनसंपर्क अभियान के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्रामीणों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उनकी समस्याओं एवं शिकायतों की जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा सड़क, पेयजल, बिजली, आवास तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दे उठाए गए, जिन पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर सतत निगरानी रखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं और विकास कार्यों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े का स्वागत किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मुख्यमंत्री बताये मोदी 12 साल में कितने वादे पूरे किया: बैज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों की बखान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने झूठ का पुलिंदा बताया है। तीन बार सरकार चलाने का अवसर मिलने के बाद भी भाजपा और मोदी देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल साबित हुये है। रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा सभी में मोदी सरकार की नीतियों ने देश को निराश किया। मोदी सरकार के 12 सालों के अपने कार्यकाल में हर क्षेत्र में विफल साबित हुई। बात पांच ट्रिलियन इकोनामी करते है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत दुनिया के 10 देशों में कहीं नहीं है। डॉलर के बदले रुपये की कीमत घटती जा रही है, 1 डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 95 रू. हो गयी है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत 105 वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बताये मोदी 12 साल में कितने वादे पूरे किया? मोदी ने 12 सालों के कार्यकाल में 1 भी वादे को पूरा नहीं किया। मोदी ने 12 सालों के कार्यकाल में अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा देश की जनता से वादा किया था।

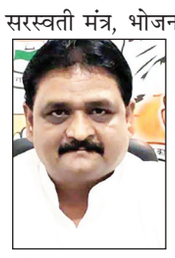

स्कूलों में आरएसएस का एजेंडा नहीं थोपा जाना चाहिए : शुक्ला

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए तीन विभिन्न प्रकार के मंत्र का गान अनिवार्य किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक का गायन तो उचित है लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र इन सब की अनिवार्यता क्यों की गयी है? सरकार स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने पर तुली है। आरएसएस के एजेंडे को सरकारी स्कूलों में थोपा जाना गलत है। सरकारी स्कूलों में देश के हर धर्म, हर जाति और हर साम्प्रदायिक के लोग पढ़ने आते है, हर वर्ग के पढ़ाई करते है। इस निर्णय से कुछ लोगों की आपत्ति होगी, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। हिन्दुस्तान सर्वधर्म समभाव वाला देश है। संवैधानिक रूप से भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। स्कूलों में धर्म विशेष के आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आजादी के बाद से हमारी शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के साथ शिक्षा दी जाती रही है। सामाजिक अध्ययन, संस्कृत एवं मातृभाषा जैसे विषयों में विद्यार्थी सभी सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करते रहे है।

प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर बिजली मांग रहे है, कहाँ है सुशासन?: ठाकुर

रायपुर। गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लाक के ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर बिजली मांगने को सरकार की नाकामी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार सुशासन तिहार मना रही है सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, वहीं गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लाक के 8 ग्राम पंचायतों 48 गांवों के 500 से अधिक ग्रामीण प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर बिजली मांग रहे है, ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ग्रामीणों का आरोप है सुशासन तिहार में उनकी सुनवाई नहीं हुई है। फिर सुशासन तिहार का क्या औचित्य है? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीणों को जनवरी में प्रशासन ने बिजली समस्या खत्म करने का आश्वासन दिया था लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया। बल्कि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने की बात कर गुमराह कर रहे है। पूर्व सरकार के दौरान सोलर प्लांट लगाकर बिजली पहुंचाई गई थी। अब सरकार जब घर-घर सोलर पैनल लगाने प्रेरित कर रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा: वंदना

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नव विवाहित नकली मंगल सूत्र दिया जाना भ्रष्टाचार की हद है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में हुये सामूहिक कन्या विवाह में शामिल विवाहित जोड़ो के लिये जो मंगल सूत्र चोरी का बताकर दिया गया था, वह नकली निकला। इसके पहले भी महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में भ्रष्ट गड़बड़िया कर चुका है। सरकार विवाह जैसे संवेदनशील मामले में भ्रष्टाचार करके लोगो की भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पंडाल का घोटाला सामने आया था। बिना टेंडर के काम दिया गया था, अब तो दहेज का सामान भी नकली दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पैसे कमाने की भूख में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में ऐसे जोड़ो को शामिल किया जाता है, जो पहले से विवाहित है, अब उनकी फिर से शादी करवा कर दहेज एवं प्रोत्साहन राशि में घोटाला किया जाता है।प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग तो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है।

नए निवेश का दावा झूठा, उद्योग व्यवसाय दम तोड़ रहे हैं: वर्मा

रायपुर। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में 9580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के सरकारी दावों को भ्रामक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार अपनी अक्षमता छुपाने के लिए केवल फर्जी दावें करती है हकीकत यह है कि नए निवेश तो दूर इस सरकार की गलत नीतियों के चलते छत्तीसगढ के पारंपरिक उद्योग बंद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया घुम आए, डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अमेरिका गए, औद्योगिकरण और नए निवेश के लिए विदेशी उद्यमियों को आमंत्रित करने के बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन नतीजा शून्य रहा। जमीनी हकीकत सरकार के दावे के विपरीत है, नए उद्योग लगना तो दूर भाजपा सरकार की दुर्भावना पूर्वक नीतियों के चलते पहले से संचालित उद्योग दम तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जून 2025 तक 18940 पंजीकृत कम्पनियां संचालित थी, जिसमें से 4288 कम्पनियां बंद क्यों हो गई? यहां पूर्व में संचालित स्पंज आयरन, रोलिंग मिलें, राइस मिल, सहकारी शक्कर कारखाने, एथेनॉल प्लांट सरकार की उपेक्षा और उद्योग विरोधी नीतियों के चलते बंद हो गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सतत प्रयासों से साकार हुआ दशकों पुराना सपना

इतिहास में पहली बार रेल मानचित्र पर उभरेगा जशपुर

रायपुर । जशपुर जिले के विकास इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने के साथ ही जशपुर को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह केवल एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई आधारशिला है।

लगभग 291.881 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से प्रारंभ होकर जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। परियोजना के क्रियान्वयन से जशपुर जिला सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में विकसित की जा रही आधुनिक आधारभूत संरचना तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों का परिणाम है। वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई जा रही रेल संपर्क की मांग अब साकार होने की दिशा में निर्णायक चरण में पहुंच गई है। रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी. अ.-04062026-273148
CG-CG-E-04062026-273148
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2764] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948
No.2764] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JVAISTHA 14, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना
बिलासपुर, 4 जून, 2026

का.आ. 2858(अ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ...

सारिणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
1.	धरमजयगढ़- पत्थलगांव लोहरदगा के बीच नई लाईन (291.881 कि.मी.)

[फा.सं. डीसीई/सी-1/ बीएसपी / नई लाईन / धरमजयगढ़ लोहरदगा /37ए]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
सीपीआर/10/201

अधिसूचना के अनुसार रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही परियोजना औपचारिक रूप से प्रभावशील हो गई है।

प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध जशपुर जिला अब तक रेल संपर्क से वंचित था। परिवहन के लिए मुख्यत: सड़क मार्ग पर निर्भरता के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

नई रेल लाइन के निर्माण से जिले की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोगों को सुरक्षित, सुलभ तथा किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

रेल संपर्क स्थापित होने से जशपुर के कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, सब्जियां और बागवानी उत्पादों के लिए पहचान रखने वाले इस क्षेत्र के किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। परिवहन लागत कम होने से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही व्यापार और लघु उद्योगों को विस्तार का नया अवसर मिलेगा।जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने वन क्षेत्रों, जलप्रपातों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के लिए विशेष पहचान रखता है।

डीएमएफ की खनिज ज्योति योजना से खुलेगी उच्च शिक्षा की राह

रायपुर। आर्थिक अभाव अब खनन से प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को दी जा रही प्राथमिकता के अनुरूप तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से जिला खनिज संस्थान न्यास , रायगढ़ द्वारा खनिज ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुँचाने के इसी उद्देश्य के साथ खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका

मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी

खनन प्रभावित विद्यार्थी की उच्च शिक्षा बाधित न हो। इस योजना के अंतर्गत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नियमित स्नातक (यू.जी.), स्नातकोत्तर (पी.जी.), इंजीनियरिंग, मेडिकल (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.), विधि, प्रबंधन (एम.बी.ए.), डिप्लोमा एवं अन्य कृषि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 20 स्वीकृत सीटों के लिए संचालित है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक अनिवार्य रूप से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित घोषित ग्रामों या नगरीय निकायों का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके परिवार का नाम राज्य शासन की चालू बी.पी.एल. अथवा अंत्योदय सूची में दर्ज होना चाहिए और वैध राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.